पोलैंड

भारत-यूरोप श्रमिक प्रवासन

जनवरी 2023

GMDAC
IOM's Global Migration Data Analysis Centre

IOM
UN MIGRATION

Indian Council of World Affairs

इस प्रकाशन में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के निजी विचार हैं और यह आवश्यक नहीं कि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन (आईओएम) के विचारों को दर्शाते हों। नियोजित पदनाम तथा पूरे प्रकाशन की अंतर्वस्तु किसी भी देश, क्षेत्र, शहर या क्षेत्र, या उसके अधिकारियों की कानूनी स्थिति, या उसकी सीमाओं के संबंध में आईओएम की राय की अभिव्यक्ति नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन इस सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्ध है कि मानवीय एवं व्यवस्थित प्रवासन से प्रवासियों और समाज दोनों को लाभ होता है। अंतरसरकारी संगठन होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपने भागीदारों के साथ मिलकर निम्न कार्य करता है: प्रवासन की परिचालन चुनौतियों का सामना करने में सहायता करना; प्रवासन संबंधी मुद्दों का अग्रिम बोध; प्रवासन के ज़रिए सामाजिक एवं आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना; और प्रवासियों की मानवीय गरिमा एवं भलाई को अनुरक्षित रखना।

यह प्रकाशन विदेश मंत्रालय (एमईए), भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए), और वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र (जीएमडीएसी) द्वारा प्रदान किए गए समर्थन से संभव हुआ है। यहां व्यक्त की गई राय लेखक की हैं और जरूरी नहीं कि वे परियोजना भागीदारों के विचारों को प्रतिबिंबित करें।

प्रकाशक: अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन
17 रूट डेस मोरिलॉन्स
पी.ओ. बॉक्स 17
1211 जिनेवा 19
स्विट्ज़रलैंड
दूरभाष: +41 22 717 9111
फैक्स: +41 22 798 6150 ईमेल: hq@iom.int वेबसाइट: www.iom.int

लेखक: मिशेल पौलेन, ऐनी हर्म और गिआम्बतिस्ता कैंटिसानी
परियोजना समन्वयक: संजय अवस्थी और सुरक्षा चन्द्रशेखर
परियोजना भागीदार: विदेश मंत्रालय (एमईए), भारतीय वैश्विक परिषद (आईसीडब्ल्यूए), वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र (जीएमडीएसी)
कॉपी संपादक: त्रिदिशा दत्ता
लेआउट कलाकार: युक्ति प्रिंट्स

कवर पेज की छवि का स्रोत: फ्रीपिक

© आईओएम 2023

कुछ अधिकार सुरक्षित हैं। यह प्रकाशन क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन-नॉन-कमर्शियल-नोडेरिव्स 3.0 आईजीओ लाइसेंस (सीसी बाय-एनसी-एनडी 3.0 आईजीओ) के तहत उपलब्ध कराया गया है।*

अधिक जानकारी के लिए कृपया कॉपीराइट एवं उपयोग की शर्तें देखें।

इस प्रकाशन का उपयोग, प्रकाशन या पुनर्वितरण ऐसे उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो मुख्यतः व्यावसायिक लाभ या मौद्रिक मुआवजे हेतु हों, लेकिन शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उदाहरण के लिए पाठ्यपुस्तकों में प्रस्तुत किए जाने हेतु।

अनुमतियाँ: व्यावसायिक उपयोग या अन्य अधिकारों एवं लाइसेंसिंग के लिए publications@iom.int पर अनुरोध किया जाना चाहिए।

* *https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/igo/legalcode*

पोलैंड

भारत-यूरोप श्रमिक प्रवासन

जनवरी 2023

GMDAC
IOM's Global Migration Data Analysis Centre

IOM
UN MIGRATION

Indian Council of World Affairs

अंतर्वस्तु

तालिका

संक्षेपाक्षर की सूची 7

कार्यकारी सारांश 8

1. आर्थिक एवं जनसांख्यिकी रूपरेखा 10
   - 1.1 आर्थिक गतिविधि एवं प्रमुख उभरते क्षेत्र 10
   - 1.2 श्रम बल की विशेषताएँ 16
   - 1.3 पोलैंड में भारतीयों का आप्रवासन 16

2. गतिशीलता मार्ग 20
   - 2.1 आप्रवासन एवं वीज़ा नीति 20
   - 2.2 भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते 21

3. कल्याण एवं एकीकरण नीतियां 23
   - 3.1 राष्ट्रीय स्तर की पहल 23
   - 3.2 स्थानीय स्तर की पहल 24

4. कार्यप्रणाली 26

5. मुख्य सूचनार्थी साक्षात्कार निष्कर्ष 27
   - 5.1 पोलैंड में श्रम बाज़ार के अवसर 27
   - 5.2 श्रमिक आप्रवासियों की उत्पत्ति के देश के रूप में भारत 31
   - 5.3 विदेशी कामगारों का एकीकरण 34
   - 5.4 प्रवासी भारतीयों के विचार 35

6. निष्कर्ष 37
   - 6.1 प्रमुख निष्कर्ष 37
   - 6.2 सीमाएँ 38

परिशिष्ट 39

आभारोक्ति

यह रिपोर्ट आईओएम डेवलपमेंट फंड (आईडीएफ) समर्थित परियोजना के अंतर्गत किया गया था, जिसका शीर्षक "भारत में सूचना आधारित डेटा एवं प्रवासी केंद्रित प्रवासन प्रबंधन ढांचे का सुदृढ़ीकरण" था। यह परियोजना आईओएम इंडिया के पूर्ववर्ती भारत प्रवासन केंद्र, भारतीय वैश्विक परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के प्रवासन, गतिशीलता और प्रवासी अध्ययन केंद्र (सीएमएमडीएस) और वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र की एक संयुक्त पहल है।

लेखक पूरी परियोजना में उनके निरंतर समर्थन एवं अमूल्य प्रतिक्रिया के लिए वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र (जीएमडीएसी), और एशिया एवं प्रशांत के आईओएम क्षेत्रीय कार्यालय को धन्यवाद देते हैं। हम रिपोर्ट को तैयार करने के प्रत्येक चरण में बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं समर्थन के लिए पोलैंड दूतावास, नई दिल्ली की सराहना करते हैं।

विषय वस्तु पर उनकी तकनीकी विशेषज्ञता हेतु आईओएम मुख्यालय, यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र के लिए आईओएम क्षेत्रीय कार्यालय और आईओएम पोलैंड के प्रतिनिधियों को भी विशेष धन्यवाद। रिपोर्ट को तैयार करने में डॉ. मीरा सेठी, डॉ. हिक्की मैटिला और श्री पॉल क्लेवेट के व्यक्तिगत इनपुट एवं योगदान से भी काफी लाभ हुआ है।

संक्षेपाक्षर

ईईए यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र

ईयू यूरोपीय संघ

जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद

जीयूएस पोलैंड का केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय

आईसीएम भारतीय प्रवासन केंद्र

आईसीडब्ल्यूए भारतीय वैश्विक परिषद

आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन

आईटी सूचना प्रौद्योगिकी

एमईए विदेश मंत्रालय, भारत

एमआईपीईएक्स प्रवासी एकीकरण नीति सूचकांक

एनजीओ गैर सरकारी संगठन

ओईसीडी आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन

पीजेडपीबी निर्माण नियोक्ताओं की पोलिश एसोसिएशन

टीसीएन तीसरे देश के नागरिक

डब्ल्यूएचओ विश्व स्वास्थ्य संगठन

कार्यकारी सारांश

यह शोध आईओएम डेवलपमेंट फंड (आईडीएफ) समर्थित परियोजना के अंतर्गत किया गया था, जिसका शीर्षक "भारत में सूचना आधारित डेटा एवं प्रवासी केंद्रित प्रवासन प्रबंधन ढांचे का सुदृढ़ीकरण" था। यह आईओएम इंडिया के पूर्ववर्ती भारत प्रवासन केंद्र, भारतीय वैश्विक परिषद, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के प्रवासन, गतिशीलता और प्रवासी अध्ययन केंद्र (सीएमएमडीएस) और वैश्विक प्रवासन डेटा विश्लेषण केंद्र की एक संयुक्त पहल है। इस शोध का उद्देश्य भारत से, विशेषकर यूरोप में, अंतर्राष्ट्रीय श्रम प्रवास हेतु उभरते अवसरों को समझना है। साउथ ईस्ट माइग्रेशन फाउंडेशन के एक उद्यम इंडिया माइग्रेशन नाउ के साथ प्रासंगिक माध्यमिक अनुसंधान करने, प्रमुख सूचनार्थी हितधारक साक्षात्कार करने और देश एवं क्षेत्र-विशिष्ट रिपोर्ट तैयार करने हेतु अनुबंध किया गया था।

यह रिपोर्ट पोलैंड पर एक गहन विवरण पेश करती है, जिसमें श्रम बाजार की स्थितियों, कौशल की कमी, कोवड-19 महामारी के प्रभाव तथा देश में आप्रवासन को नियंत्रित करने वाले मौजूदा नीतियों पर चर्चा की गई है। एक गहम समीक्षा से आर्थिक रुपरेखा, जनसांख्यिकीय एवं प्रवासन की प्रवृत्तियों, रुचि के प्रमुख क्षेत्रों और पोलैंड के लिए गतिशीलता मार्गों को जानकर पोलैंड के श्रम बाजार को समझने में मदद मिली। इसके बाद, द्विपक्षीय समझौतों, राष्ट्रीय तथा उप-राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और कोविड-19 के दीर्घकालिक श्रम बाजार प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक अधिक विस्तृत नीति समीक्षा की गई। इस नीति समीक्षा से हमें पोलैंड के श्रम बाजार और भारत के साथ इसके प्रवासन कॉरिडोर को समझने में मदद मिली।

इसके अलावा, यह रिपोर्ट भारत तथा पोलैंड में मौजूद क्षेत्रीय हितधारकों के दृष्टिकोण और सिफारिशों को सामने रखकर पोलैंड के श्रम बाजार को समझने में सहायता करती है। ये हितधारक परामर्श नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक भारत और पोलैंड में आयोजित किए गए थे। सरकारी विभागों, बहुपक्षीय एजेंसियों, नियोक्ता संघों, ट्रेड यूनियनों, अनुसंधान संगठनों एवं विशेषज्ञों जैसी विभिन्न श्रेणियों की पहचान करने हेतु शुरुआत में हितधारकों की मैपिंग की गई थी। इसके अलावा, भारतीय प्रवासियों, कामकाजी पेशेवरों और छात्रों को पोलैंड में प्रवास के अपने-अपने अनुभव बताने के लिए हितधारक परामर्श में शामिल किया गया था। हितधारक परामर्श का उपयोग पोलैंड श्रम बाजार में अधिक जानकारी प्राप्त करने और साहित्य एवं नीति समीक्षा निष्कर्षों को मान्य करने हेतु किया गया था। कुल 21 हितधारक परामर्श किए गए, जिनमें भारतीय हितधारकों के साक्षात्कार भी शामिल हैं जिनकी अंतर्दृष्टि पोलैंड देश की रिपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण थी।

हितधारकों के परामर्श से प्राप्त मुख्य निष्कर्ष

पोलैंड में श्रम की कमी एवं रुचि के प्रमुख क्षेत्र

- जनसंख्या की बढ़ती उम्र और पोलैंड के नागरिकों के दूसरे देशों में प्रवास के साझा प्रभाव की वजह से पोलैंड को विभिन्न क्षेत्रों में श्रम की कमी का सामना करना पड़ रहा है।

- कृषि, निर्माण, आतिथ्य, परिवहन, रसद एवं देखभाल जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ आईटी और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च कौशल वाले उद्योगों को ऐसी कमी का सामना करना पड़ रहा है जो पड़ोसी देशों के अप्रवासियों ने पूरी की हैं।

श्रम बाजार

- यूक्रेन और बेलारूस जैसे देशों से सबसे अधिक प्रवासी आते थे, लेकिन मोल्दोवा, जॉर्जिया एवं रूस सहित अन्य देश भी महत्वपूर्ण हैं।

- एशियाई मूल के देशों में, चीन और वियतनाम पिछले कुछ दशकों में नेपाल, भारत और बांग्लादेश जैसे उभरते देशों के रूप में महत्वपूर्ण रहे हैं।

- यूक्रेन में हालिया युद्ध की वजह से पोलैंड में यूक्रेन के नागरिकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। हितधारकों का मानना है कि इससे अन्य देशों से आप्रवासन प्रभावित होगा क्योंकि अब पोलैंड के पास स्थानीय आबादी के साथ मजबूत सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंधों के साथ अधिक श्रम शक्ति होगी।

भारतीय आप्रवासियों की भूमिका

- पोलैंड में भारत के अपेक्षाकृत आप्रवासी कम है, लेकिन व्यापार (थोक, आतिथ्य) और शिक्षा क्षेत्र दोनों में इसकी जड़ें मजबूत हैं। वे खुदरा व्यवसायों, रेस्तरां और खानपान एवं आईटी जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

- विनिर्माण, निर्माण और प्रशासनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अर्ध-कौशल और अस्थायी पद हाल ही में भारतीयों को मिले हैं, और पिछले 3 वर्षों में जारी किए गए परमिटों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

- हालाँकि, यूक्रेनी शरणार्थियों की नई आमद को देखते हुए, आईटी और व्यवसाय जैसे क्षेत्र भारतीयों के लिए भविष्य के सबसे अच्छे रास्ते हो सकते हैं।

- अंग्रेजी शिक्षा की उपलब्धता और छात्रों के लिए अंशकालिक काम के नियमों में छूट को देखते हुए, छात्रों का प्रवास भारतीयों के लिए एक रास्ता खुला है।

हितधारकों के समक्ष चुनौतियाँ

- आप्रवासन के प्रति जनता के नकारात्मक रवैये के कारण, सरकार बढ़ती श्रम की कमी पर कोई ठोस कदम उठाने में सक्रिय नहीं रही है।

- किसी व्यापक प्रवासन नीति का अभी तक आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं किया गया है।

- चूंकि यूक्रेनी शरणार्थी आबादी से अब मौजूदा कुछ कमी कुछ हद तक कम होने की उम्मीद है, इसलिए सरकारी स्तर पर अन्य आप्रवासी समूहों के लिए ऐसी नीति कुछ समय तक वास्तविकता नहीं हो सकती है।

- निजी क्षेत्र के संघ और नियोक्ता समुदाय भारत जैसे देशों के लिए द्विपक्षीय सहयोग हेतु एक अच्छा विकल्प देते हैं।

विदेशी कामगारों का एकीकरण

- पोलैंड में अप्रवासी समुदायों के लिए व्यापक एकीकरण नीति का अभाव है।

- सामने आई कुछ चुनौतियों में सांस्कृतिक आघात, भाषा कौशल की कमी, और समुदाय द्वारा सामना किया जाने वाला भेदभाव (हालाँकि वारसॉ, क्राको, व्रोकला एवं ग्दान्स्क जैसे प्रसिद्ध प्रवासी-गंतव्य शहरों में इसका अनुभव कम है) थीं।

- अल्पकालिक आप्रवासियों और पोलैंड को पारगमन का गंतव्य मानने वालों के लिए, क्योंकि वे यूरोप में कहीं अन्य प्रवास करना चाहते हैं, परिवार से फिर से मिलने और दीर्घकालिक एकीकरण की चुनौतियाँ कम प्रासंगिक हैं।

- इन चुनौतियों को कम करने में मौजूदा प्रवासी संघों के साथ सहयोग के महत्व पर हितधारकों द्वारा प्रकाश डाला गया।

1 | आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय रूपरेखा

1.1 आर्थिक गतिविधि एवं प्रमुख उभरते क्षेत्र

व्यापक स्तर पर विकास की सफलता का उदाहरण माने जाने वाले पोलैंड, जिसका 1989 में सोवियत संघ के पतन के बाद उदारीकरण हुआ था, में विगत तीन दशकों में जबरदस्त आर्थिक विकास देखा गया है, जिससे यह 15 वर्षों में मध्यम से उच्च आय वर्ग में पहुंच गया है।[1] 2008 के वित्तीय संकट के तुरंत बाद सकारात्मक वृद्धि वाले दुनिया भर के एकमात्र देशों में से एक, पोलैंड वर्तमान में बेल्जियम और स्कैंडिनेवियाई देशों जैसे देशों को पीछे छोड़ते हुए यूरोपीय संघ में छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था (जीडीपी के अनुसार) है।[2] इस देश को कोविड-19 महामारी के दौरान अपेक्षाकृत कम आर्थिक नुकसान हुआ, जिससे दुनिया भर के देश बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। 2020 में, पोलैंड में 5.5 प्रतिशत ओईसीडी औसत की तुलना में 3.5 प्रतिशत की जीडीपी संकुचन देखा गया, और यूरोस्टेट डेटा के अनुसार इसकी बेरोजगारी दर 2021 में सबसे कम (3.1%) रही, जिसकी वजह इसकी अर्थव्यवस्था में सेवाओं की तुलना में विनिर्माण पर अधिक निर्भरता को माना जाता है।[3]

पोलैंड मानव विकास सूचकांक (0.8) में 35वें स्थान पर है, जिसमें 1990-2020 के बीच लगातार सुधार देखा गया है, जिसमें स्कूली शिक्षा के 16.3 अपेक्षित वर्ष, 31623 यूएसडी (पीपीपी) की सकल राष्ट्रीय आय और 0.813 की असमानता समायोजित एचडीआई है।[4] विश्व बैंक के 2020 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स पर 76.4 के स्कोर के साथ यह देश 40वें स्थान पर है,[5] लेकिन रुल ऑफ लॉ इंडेक्स में 0.66 के स्कोर और 28वें के वैश्विक रैंक के साथ एक रैंक नीचे आ गया है। विश्व बैंक के नए आंकड़ों के के अनुसार, सर्विस सेक्टर का पोलैंड के सकल घरेलू उत्पाद में 57.6 प्रतिशत हिस्सा है, जिससे 59 प्रतिशत आबादी को रोजगार मिलता है। उद्योग क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 28.6 प्रतिशत (रोजगार 32%) का है, और कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में 2.3 प्रतिशत (9% रोजगार) योगदान है। पोलैंड में आर्थिक विकास हेतु कुछ प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण, निर्माण, ऊर्जा, खनन, परिवहन एवं रसद, कृषि, खुदरा और व्यावसायिक सेवाएँ शामिल हैं। हालाँकि, इस सभी में उत्पादकता में सुधार की आवश्यकता है और उन्हें "जनसांख्यिकीय दबाव" - बढ़ती आबादी एवं घटती घरेलू कामकाजी आबादी की संभावना का खतरा है।[6]

---

1 World Bank (2017), Lessons from Poland, Insights for Poland, Retrieved from: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28960.

2 World Bank Statistics (2020), Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=EU&most_recent_value_de- sc=true.

3 Bukowski & Paczos (2021), Why is Poland's economy emerging so strongly from the pandemic? LSE Blogs & Notes from Poland, Retrieved from https://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2021/05/19/why-is-polands-economy-emerging-so-strongly-from-the-pandemic-a-comparison-with-the- uk/.

4 UNDP (2020), Human Development Report 2020, Retrieved from: http://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking.

5 World Bank (2020), Doing Business 2020. Retrieved from: https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/country/p/poland/POL. pdf.

6 McKinsey (2015), Poland 2025: Europe's New Growth Engine, Retrieved from: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/economic%20studies%20temp/our%20insights/how%20poland%20can%20become%20a%20european%20growth%20engine/poland%20 2025_full_report.ashx.

पोलैंड के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (जीयूएस) की श्रम सांख्यिकी पर नवीनतम रिपोर्ट[7] 2019 से वर्तमान तक के बीच विनिर्माण, निर्माण, व्यापार एवं मोटर वाहन मरम्मत, परिवहन व भंडारण, आवास एवं खानपान (आतिथ्य), वित्तीय और बीमा गतिविधियों, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में रिक्त नौकरी पर प्रकाश डालती है। 21,000 और 8,900 रिक्तियों के साथ विनिर्माण एवं निर्माण, में सबसे अधिक रिक्ति थी। परिवार, श्रम एवं सामाजिक नीति मंत्रालय द्वारा हर साल तैयार की जाने वाली एक रिपोर्ट, ऑक्यूपेशनल बैरोमीटर में भी इसे उजागर किया गया है। इसमें कमी, अधिशेष एवं संतुलित व्यवसायों की क्षेत्रीय रूप से अलग-अलग सूची दी गई है। नई ऑक्यूपेशनल बैरोमीटर निर्माण, विनिर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, परिवहन और रसद एवं शिक्षा को उन क्षेत्रों के रूप में इंगित करती है जहां अधिक कमी वाले व्यवसाय हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, 2022 में कमी वाले व्यवसायों में 29 व्यावसायिक श्रेणियां शामिल थीं[8], जिनमें देखभाल कार्य, निर्माण, विनिर्माण, शिक्षा और रसद जैसे क्षेत्रों से लेकर लेखांकन एवं बहीखाता क्लर्क, एम्बुलेंस कर्मचारी, बेकर्स, राजमिस्त्री और प्लास्टर, बस चालक, कंक्रीट प्लेसर, कंक्रीट फिनिशर और संबद्ध श्रमिक, निर्माण स्थापना असेंबलर, लकड़ी के हस्तशिल्प श्रमिक, स्वतंत्र लेखाकार, चिकित्सा डॉक्टर, बुजुर्गों एवं विकलांगों की देखभाल करने वाले सामाजिक कार्य पेशेवर, स्टॉक क्लर्क, व्यावहारिक व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु शिक्षक, और ट्रक चालक जैसे पेशे शामिल थे।[9]

चित्र 1: सभी प्रांतों में सर्वाधिक प्रचलित कमी, ऑक्यूपेशनल बैरोमीटर 2021

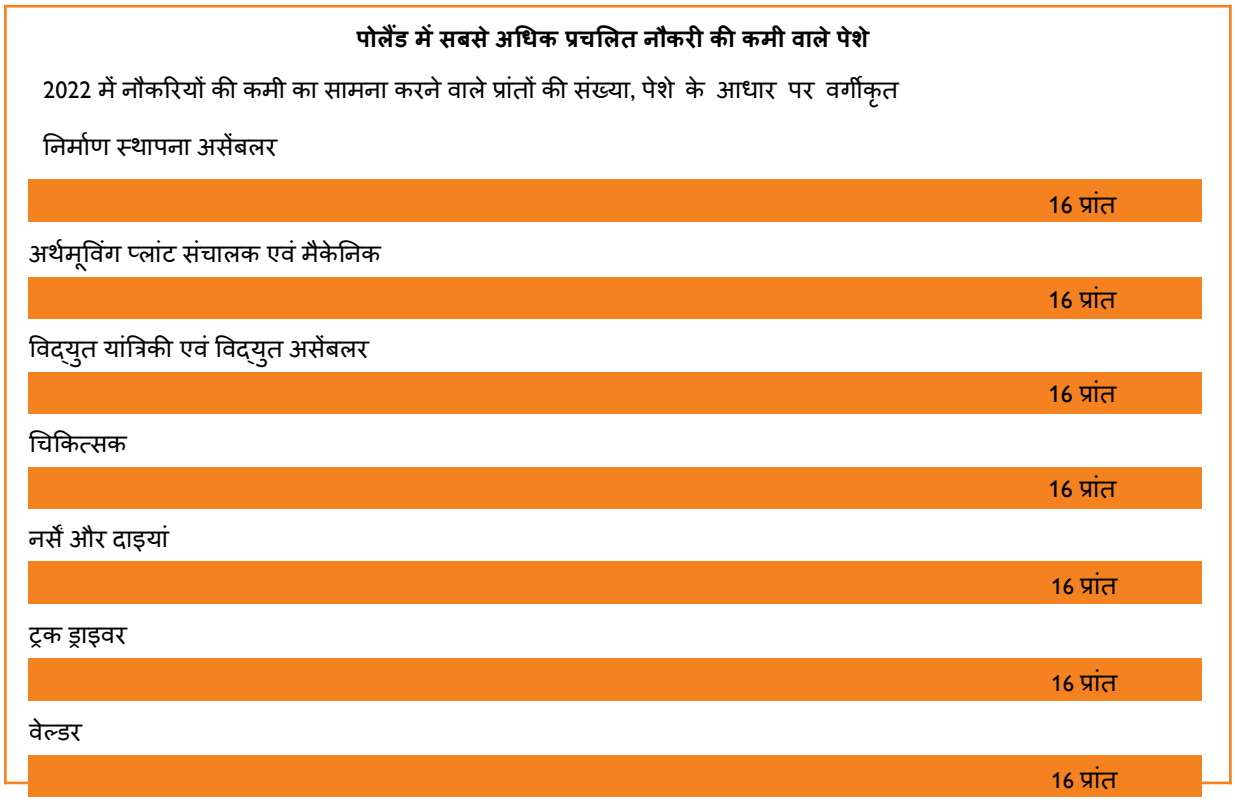

7 Yearbook of Labour Statistics 2021, Central Statistical Office, Poland (GUS), Retrieved from https://stat.gov.pl/en/topics/statistical-yearbooks/ statistical-yearbooks/yearbook-of-labour-statistics-2020,10,8.html.

8 Occupational Barometer 2021 for Poland (2020), Ministry of Family, Labour, and Social Policy, Government of Poland, Retrieved from: https:// wupkrakow.praca.gov.pl/documents/67976/13865790/Occupational%20barometer%202020.%20Summary%20Survey%20Raport%20for%20Poland./9053337d-5fa9-4875-aebf-6333c18dbc4d?t=1614062919000.

9 The full list as per the Occupational Barometer 2021: accounting and bookkeeping clerks, ambulance workers, bakers, bricklayers and plaster- ers, bus drivers, concrete placers, concrete finishers and related workers, construction installation assemblers, construction joiners and carpen- ters, construction workers, cooks, earthmoving plant operators and mechanics, electrical mechanics and electrical assemblers, finishing work technologists in building trades, handicraft workers in wood and joiners, independent accountants, medical doctors, metal working machine tool setters and operators, motor vehicle mechanics and repairers, nurses and midwives, pavers, physiotherapy technicians and assistants, psycholo- gists and psychotherapists, roofers and sheet metal workers in building trades, social work professionals caring for the elderly and disabled, stock clerks, teachers for practical vocational training, teachers of vocational subjects, toolmakers, truck drivers, and welders.

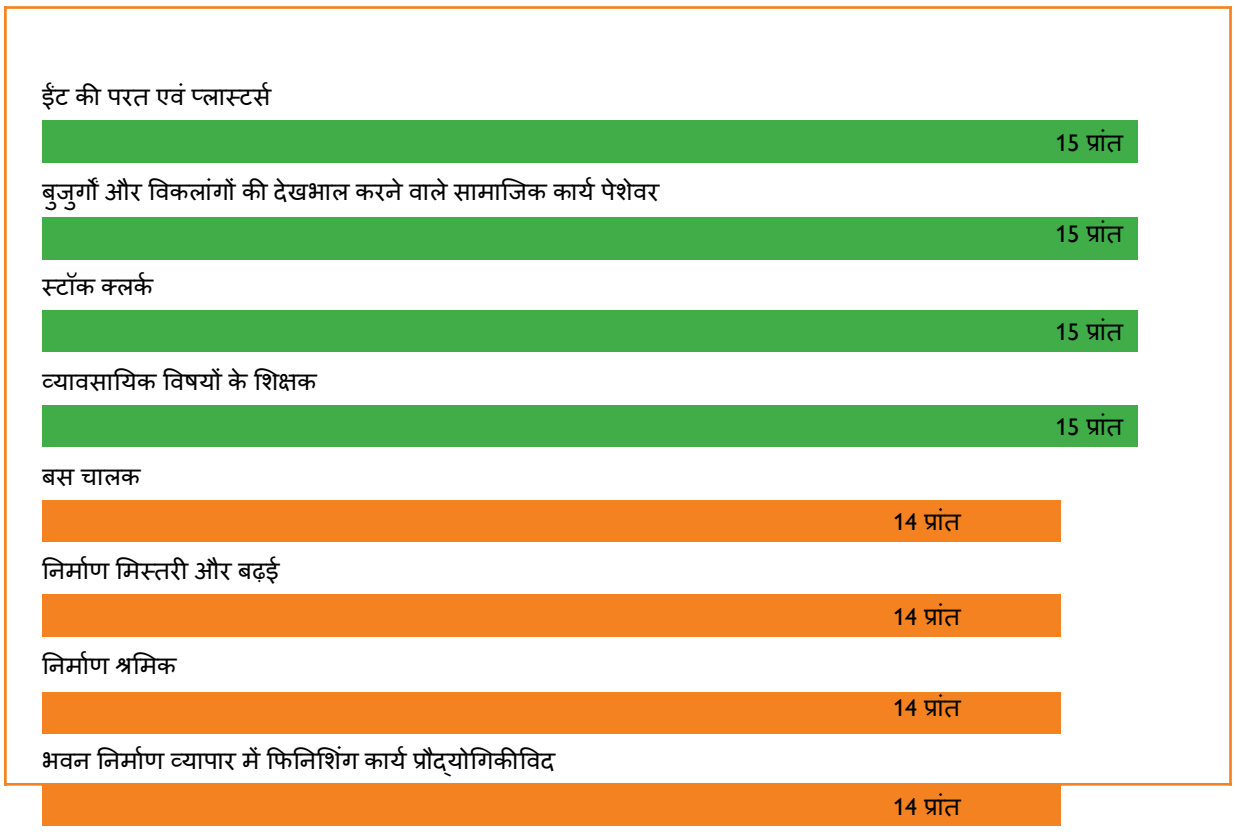

स्रोत: ऑक्यूपेशनल बैरोमीटर

चित्र 2: सभी प्रांतों में कौशल की कमी का मानचित्रण, ऑक्यूपेशनल बैरोमीटर 2021

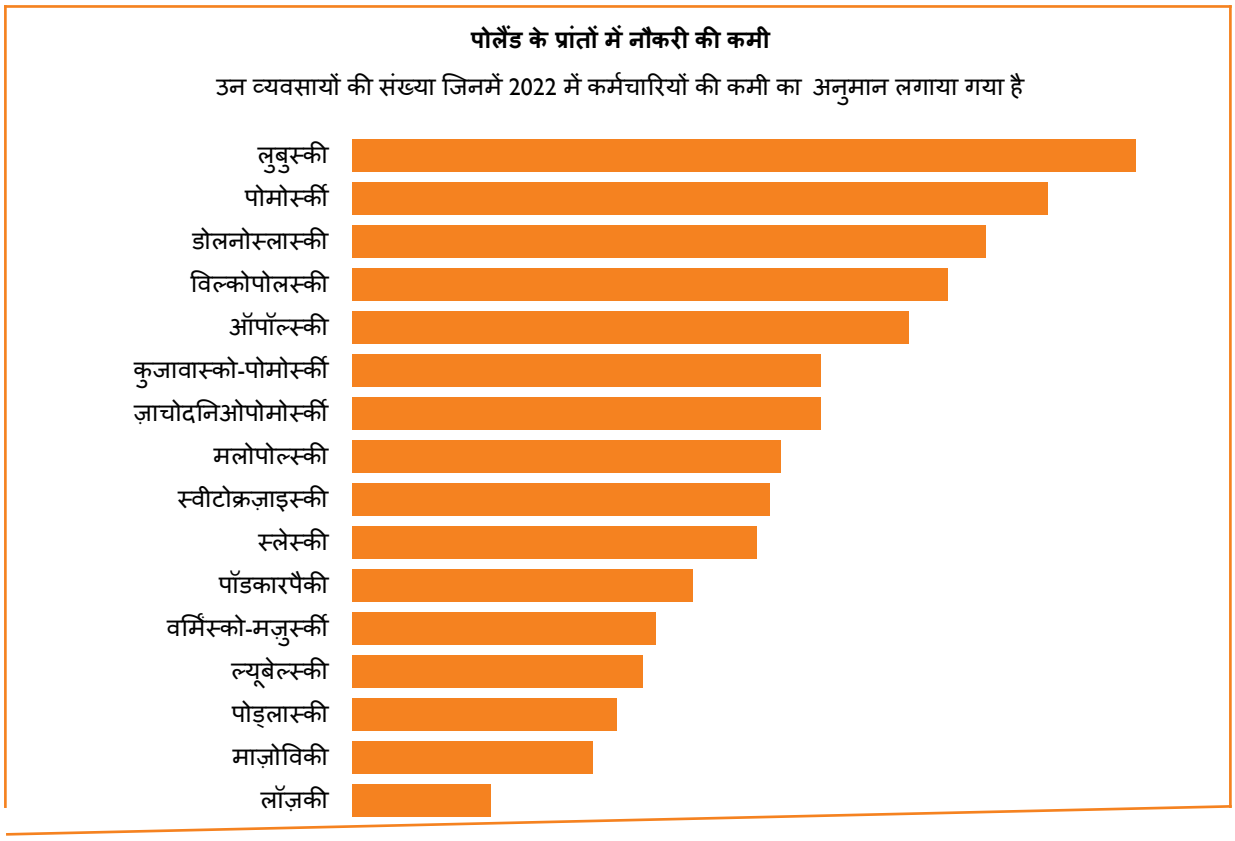

स्रोत: ऑक्यूपेशनल बैरोमीटर

1.1.1 निर्माण

पोलैंड में निर्माण एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसकी वैल्यूएशन 224.3 बिलियन पीएलएन[10] है और यह देश की जीडीपी का 9 प्रतिशत है। यूरोपीय विनिर्माण उद्योग महासंघ के अनुसार पोलिश निर्माण क्षेत्र (19%) की संचित वृद्धि पूरे यूरोप (6%) में इस क्षेत्र का एक प्रमुख चालक है।[11] इसके तीन प्रमुख उप-क्षेत्रों - रेजिडेंशियल, कमर्शियल एवं सिविल इंजीनियरिंग कार्यों - पर कोविड-19 महामारी के कारण अलग-अलग प्रभाव देखे गए हैं। हालांकि, उच्च मांग और सरकारी निवेश के कारण रेजिडेंशियल एवं सिविल इंजीनियरिंग क्षेत्र स्थिर बने हुए हैं, महामारी के दौरान कमर्शियल निर्माण पर असर पड़ा है। इससे आने वाले महीनों में अधिक क्रेडिट जोखिम उत्पन्न होने और अधिक दिवालिया होने की आशंका है। हालाँकि, पूरे सेक्टर में 2022 में 7 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की भी उम्मीद है।[12]

इस सेक्टर में श्रम बल को लेकर अलग-अलग अनुमान हैं - जबकि निजी क्षेत्र के अनुमान से ऐसा लगता है कि विनिर्माण क्षेत्र में 2020 में 426,100 श्रमिकों को रोजगार मिला है, जो 2019 की तुलना में सिर्फ 0.9 प्रतिशत अधिक है,[13] यूरोपीय निर्माण उद्योग महासंघ के आंकड़े 2019 में 1.2 मिलियन की श्रम शक्ति (900,000 कर्मचारी और 300,000 स्व-रोज़गार दर्शाते हैं।[14] कौशल की कमी इस क्षेत्र की प्रमुख चुनौती है। 2015 से यूरोपीय संघ के यूरोपीय निर्माण क्षेत्र अब्ज़र्वटॉरी की रिपोर्ट कुशल श्रमिकों (विशेषतः राजमिस्त्री और प्लास्टर) की कमी को दर्शाती है। यह भी उजागर करती है प्रवासन की भूमिका - विशेष रूप से, पोलैंड के युवा निर्माण पेशेवरों का उत्तरी और पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रवास, जिससे श्रम बाजार में कमी को आप्रवासन (विशेष रूप से यूक्रेन से) के माध्यम से पूरा किया जा सके। हालाँकि, एक हालिया समाचार रिपोर्ट से पता चलता है कि पोलिश फर्म एवं उद्यमी इस क्षेत्र में यूक्रेनियन की कमी से जूझ रहे हैं, क्योंकि कई श्रमिक अपने परिवारों की मदद करने एवं लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए यूक्रेन लौट आए हैं। विनिर्माण उद्योग नियोक्ताओं के पोलिश एसोसिएशन (पीजेडपीबी) के एक बयान से संकेत मिलता है कि क्षेत्र के 480,000 विदेशी श्रमिकों में से 80% यूक्रेनी थे।[15] निजी क्षेत्र के अनुमान इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि उच्च मांग, कुशल श्रमिकों की कम उपलब्धता और बढ़ती श्रम लागत क्षेत्र की वृद्धि में बड़ी चुनौतियां हैं। ऑक्यूपेशनल बैरोमीटर क्षेत्र में 9 प्रमुख कमी वाले व्यवसायों पर प्रकाश डालता है, जिनमें गंभीर (2015 से स्थायी घाटे में) जैसे कंक्रीट प्लेसर, फिनिशर और संबंधित श्रमिक, छत बनाने वाले एवं शीट मेटल श्रमिक शामिल हैं।[16]

1.1.2 विनिर्माण

विश्व बैंक के अनुसार, विनिर्माण पोलैंड के सबसे मजबूत क्षेत्रों में से एक है, जिसका 2019 में सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 17 प्रतिशत मूल्य वर्धित योगदान रहा है[17] और पोलैंड के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार, वैल्यूएशन के मामले में 2010 में 864130.3 मिलियन पीएलएन से बढ़कर 2019 में 1450720 मिलियन पीएलएन हो गया है।[18]

---

10 Deloitte (November 2020), Polish Construction Companies 2020: Major Players, Key Growth Drivers & Development Prospects, Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_spolki_budowlane_2020-EN.pdf.

11 European Construction Industry Federation (2021), Overall Construction Activity: Poland, Retrieved from: https://fiec-statistical-report.eu/ poland.

12 Atradius (October 2020), Industry Trends Construction: Focus on Sector Business Performance and Credit Risk.

13 Deloitte (November 2020), Polish Construction Companies 2020: Major Players, Key Growth Drivers & Development Prospects, Retrieved from: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_spolki_budowlane_2020-EN.pdf.

14 European Construction Industry Federation (2021), Overall Construction Activity: Poland, Retrieved from: https://fiec-statistical-report.eu/ poland.

15 (25 March, 2022). Polish businesses face labour shortage after Ukraine war. Retrieved from: https://www.rfi.fr/en/polish-businesses-face-la- bour-shortage-after-ukraine-war.

16 Atradius (October 2021), Industry Trends Construction: Focus on Sector Business Performance and Credit Risk; Deloitte (Novem- ber 2020), Polish Construction Companies 2020: Major Players, Key Growth Drivers & Development Prospects, Retrieved

from: https:// www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Raport_spolki_budowlane_2020-EN.pdf; Occupational Barom- eter 2020 for Poland (2019), Ministry of Family, Labour, and Social Policy, Government of Poland, Retrieved from: https://wupkrakow.
praca.gov.pl/documents/67976/13865790/Occupational%20barometer%202020.%20Summary%20Survey%20Raport%20for%20Po-land./9053337d-5fa9-4875-aebf-6333c18dbc4d?t=1614062919000.

17 World Bank Indicators, Retrieved from: https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=PL.

18 Statistical Yearbook of Industry 2021, Central Statistical Office, Poland (GUS), Retrieved from: https://stat.gov.pl/en/topics/statistical-year- books/statistical-yearbooks/statistical-yearbook-of-industry-poland-2021,5,15.html.

इसमें निजी क्षेत्र का भी वर्चस्व है, जिसका 2019 में उत्पादन में 83.2 प्रतिशत योगदान था।[19] पश्चिमी यूरोप के देशों के विपरीत, जहां हाल के दशकों में विनिर्माण पर निर्भरता कम हो गई है, पोलैंड एवं अन्य पूर्वी यूरोपीय देश विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरे हैं। पोलैंड दुनिया का 16वां सबसे बड़ा निर्माता है, जिससे यह दुनिया के विनिर्माण उत्पादन का 1 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें 370000 संस्थाएं 2.3 मिलियन (श्रम बल का 19.3%) को रोजगार देती हैं।[20] इस क्षेत्र में बहुत अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आता है और इसकी वजह विमानन, मोटर वाहन, खाद्य व पेय पदार्थ, घरेलू उपकरण, विद्युत उपकरण और धातु उत्पादों सहित कई उप-क्षेत्र हैं। उन्नत विनिर्माण जैसे उप-क्षेत्र, जिसमें उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, अभी भी छोटे हैं लेकिन इंडस्ट्री 4.0 (2016 में 'चौथी औद्योगिक क्रांति' के लिए प्रतिपादित किया गया एक शब्द था, यह बताने हेतु कि उभरती हुई तकनीक से उद्योग में कैसे क्रांति आएगी) के संदर्भ में इसका दायरा बढ़ रहा है।[21]

पोलैंड का ऑक्यूपेशनल बैरोमीटर इस क्षेत्र में 6 महत्वपूर्ण कमी वाले व्यवसायों - विद्युत यांत्रिकी एवं विद्युत असेंबलर, धातु श्रमिक, मशीन टूल सेटर्स और ऑपरेटर, हस्तशिल्प श्रमिक, उपकरण निर्माता, वेल्डर दर्जी और कपड़ा निर्माता (पिछले तीन 2016 से लगातार घाटे में हैं) की ओर इशारा करता है। निर्माण उद्योग के जैसे ही उपयुक्त प्रमाणपत्रों वाले कुशल कार्यबल की कमी एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा, कामकाज की कठिन परिस्थितियाँ, अपेक्षाकृत कम संभावनाएँ जैसे कम वेतन, अनौपचारिक काम एवं स्थानीय कामकाजी आबादी की सीमित रुचि से यह कमी और बढ़ती है। हाल के वर्षों में, अन्य पूर्वी यूरोपीय देशों के प्रवासियों को इस क्षेत्र में अधिक काम पर रखा गया है।[22]

1.1.3 स्वास्थ्य सेवा

पूरे यूरोप में, विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के संदर्भ में, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र कमी का अनुभव कर रहा है। ऐसा आपूर्ति और मांग की बाधाओं के दोहरे प्रभाव के कारण है। कामकाजी आबादी की कमी के साथ-साथ मौजूदा आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है, जो महामारी के दौरान बढ़ती स्वास्थ्य देखभाल मांगों के कारण और बढ़ गई है। यूरोपीय संघ के औसत की तुलना में कम जीवन प्रत्याशा होने के बावजूद, पोलैंड की आबादी अन्य यूरोपीय संघ के देशों की तुलना में तेजी से बूढ़ी हो रही है और अध्ययनों से पता चलता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में वित्तपोषण काफी कम है।[23] 2007 में, पोलिश सरकार ने नर्सिंग की कमी को पूरा करने हेतु एक नई नर्सिंग श्रेणी (चिकित्सा देखभालकर्ता - देखभालकर्ता नर्सों की मदद करते हैं, और उनके काम कम तकनीकी होते हैं) की शुरुआत की।[24] हालाँकि, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी वर्तमान में देश की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक बनी हुई है, जहां डॉक्टरों एवं नर्सों दोनों का अनुपात यूरोपीय संघ में सबसे कम (2018 डब्ल्यूएचओ प्रोफ़ाइल से पता चलता है कि प्रति 1000 जनसंख्या पर 5.2 नर्सें और 2.3 चिकित्सक थे) है। अतिरिक्त चुनौतियों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की तुलना में प्राथमिक देखभाल हेतु सामान्य चिकित्सकों और नर्सों की कमी शामिल है, जिनकी उपलब्धता अधिक है और स्वास्थ्य कार्यकर्ता आबादी अधिक उम्र की है।[25]

19 Ibid.

20 Euraxess (2016), The Manufacturing Sector in Europe. Labour Market Briefings Series, Retrieved from: https://cdn4.euraxess.org/sites/default/ files/labor_market_information-_manufacturing_sector.pdf.

21 McKinsey (2015), Poland 2025: Europe's New Growth Engine, Retrieved from: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20 functions/economic%20studies%20temp/our%20insights/how%20poland%20can%20become%20a%20european%20growth%20engine/poland%20 2025_full_report.ashx; International Trade Administration, US Department of Commerce (2021), Poland Country Commercial Guide: Advanced Manufacturing, Retrieved from: https://www.trade.gov/country-commercial-guides/poland-advanced-manufacturing.

22 Occupational Barometer 2020 for Poland (2019), Ministry of Family, Labour, and Social Policy, Government of Poland, Retrieved from: https:// wupkrakow.praca.gov.pl/documents/67976/13865790/Occupational%20barometer%202020.%20Summary%20Survey%20Raport%20for%2 0Po- land./9053337d-5fa9-4875-aebf-6333c18dbc4d?t=1614062919000.

23 Sowada, C. and Kowalska-Bobko, I. (2021), "Sustainability of the Polish Health Care System", Baltagi, B.H. and Moscone, F. (Ed.) The Sustain- ability of Health Care Systems in Europe(Contributions to Economic Analysis, Vol. 295), Emerald Publishing Limited, Bingley, pp. 117-137. https:// doi.org/10.1108/S0573-855520210000295012.

24 WHO Europe (2018), Strengthening Nursing in Primary Care in Poland, Retrieved from: https://www.euro.who.int/ data/assets/pdf_ file/0008/405719/POL-web-240619.pdf.

25 Żuk, P., Żuk, P., & Lisiewicz-Jakubaszko, J, (2019), Labour migration of doctors and nurses and the impact on the quality of health care in Eastern European countries: The case of Poland. The Economic and Labour Relations Review, 30(2), 307–320. https://doi. org/10.1177/1035304619847335.

एक अन्य समस्या जिससे यह कमी बढ़ती है वह है चिकित्सा पेशेवरों का अधिक प्रवास। पोलिश डॉक्टर और नर्सें उच्च वेतन, बेहतर कामकाजी परिस्थितियों और अच्छी जॉब प्रोफाइल सहित कई कारणों से अन्य यूरोपीय और ओईसीडी देशों में चले जाते हैं।[26] इससे देश में श्रम की कमी पैदा होती है जिससे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली प्रभावित है। ओईसीडी डेटा से पता चलता है कि पोलैंड में विदेशी प्रशिक्षित डॉक्टरों की वार्षिक आमद 2010 में 60 से बढ़कर 2020 में 390 हो गई, जबकि विदेशी प्रशिक्षित नर्सों की आमद 2010 में 6 से बढ़कर 2020 में 53 हो गई। वास्तविक एवं अनुमानित कमी को देखते हुए, मुख्यतः यूक्रेन और बेलारूस से हुआ यह इनफ्लो, कम हैं। ऑक्यूपेशनल बैरोमीटर के अनुसार, 2021 के लिए कमी वाले व्यवसायों में फिजियोथेरेपी तकनीशियन और सहायक, चिकित्सा डॉक्टर, बुजुर्गों और विकलांगों की देखभाल करने वाले सामाजिक कार्य पेशेवर, एम्बुलेंस कर्मचारी और नर्स व दाइयां शामिल हैं। 2021 में, पोलैंड की 380 काउंटियों में से 334 में और डॉक्टरों की भर्ती के लिए 273 में नर्स भर्ती में चुनौतियों की आशंका थी।[27]

चित्र 3: यूरोपीय संघ के देशों में स्वास्थ्य सेवा कार्यबल

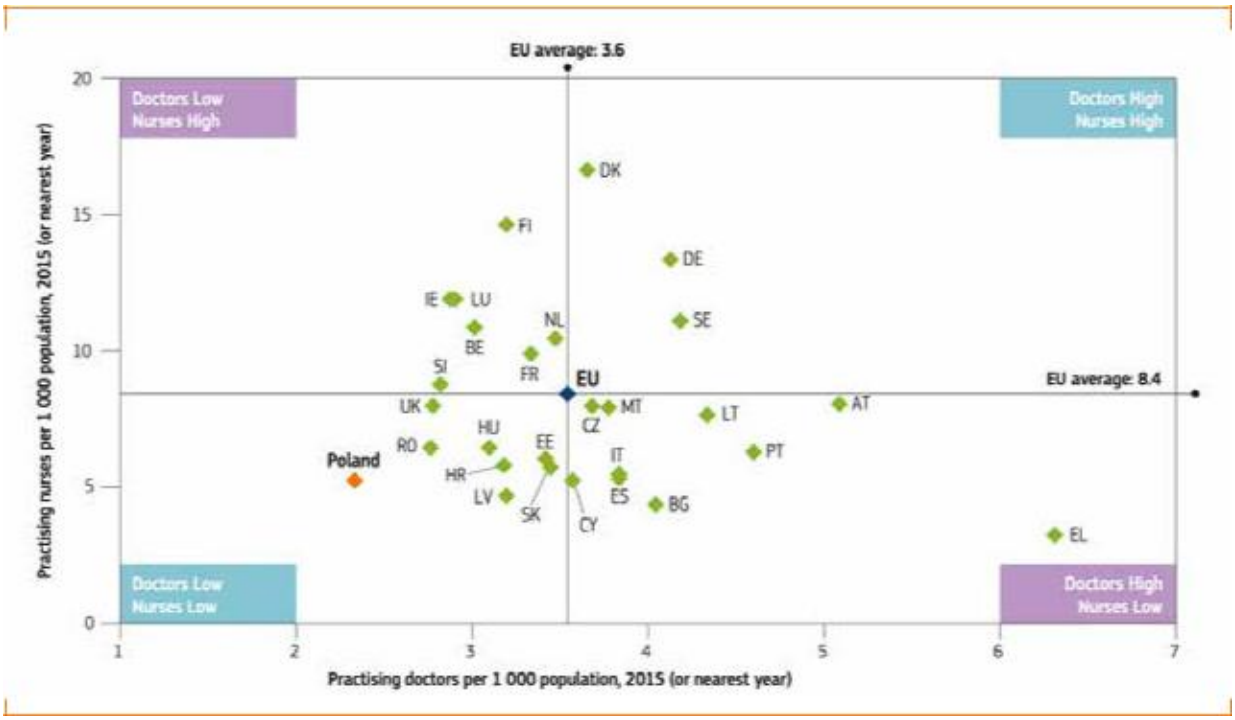

स्रोत: डब्ल्यूएचओ, 2018

1.1.4 परिवहन एवं रसद

यूरोप के भौगोलिक केंद्र में स्थित होने की वजह से पोलैंड परिवहन एवं रसद सेक्टर के लिए बेहद अनुकूल है। निजी क्षेत्र के बाजार अनुसंधान से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 2020-25 से सालाना प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है और 2017 में सकल घरेलू उत्पाद में 6 प्रतिशत का योगदान होगा। इसके उप-क्षेत्रों में, रेल में सबसे अधिक वृद्धि (22.8%) होने की उम्मीद है, इसके बाद सड़क मार्ग से (10.4%), वायु मार्ग से (9.7%), नदी द्वारा (9.2%), और समुद्री परिवहन द्वारा (7.7%) की वृद्धि होने की उम्मीद है।[28] इसका मुख्य कारण ई-कॉमर्स उद्योग में वृद्धि है, जिसका वैल्यूएशन वर्तमान में 50 बिलियन पीएलडी है और आने वाले वर्षों में तेजी से बढ़ने का अनुमान है। प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) की रिपोर्ट 2020 में अनुमान है कि 2018-22 के बीच पोलिश वाहक द्वारा संचालित मात्रा (टन भार) में 22.8 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

---

26 Ibid

27 Occupational Barometer 2020 for Poland (2019), Ministry of Family, Labour, and Social Policy, Government of Poland, Retrieved from: https://wupkrakow.praca.gov.pl/documents/67976/13865790/Occupational%20barometer%202020.%20Summary%20Survey%20Raport%20for%20Po- land./9053337d-5fa9-4875-aebf-6333c18dbc4d?t=1614062919000.

28 Mordor Intelligence (2020), Poland Frieght and Logistics Market: Growth, Trends, COVID 19 Impacts and Forecasts 2021-26, Retrieved from https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/poland-freight-and-logistics-market

हालाँकि, PwC का यह भी अनुमान है कि इस अवधि के दौरान 200,000 कर्मचारियों और ड्राइवरों की कमी होगी। डिजिटलीकरण एवं औद्योगीकरण के साथ-साथ, श्रम की कमी उन प्रमुख कारकों में से एक है जो आने वाले दशक में पोलैंड के परिवहन एवं रसद क्षेत्र को प्रभावित करेगी।[29] पोलैंड का ऑक्यूपेशनल बैरोमीटर 3 प्राथमिक कमियों की ओर इशारा करता है - स्टॉक क्लर्क, बस ड्राइवर एवं ट्रक ड्राइवर, जिनमें से अंतिम दो की 2015 के बाद से गंभीर कमी है। इसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर विदेशी भाषाओं, यांत्रिक ज्ञान जैसे उपयुक्त कौशल, और सतर्कता एवं समय प्रबंधन जैसे सॉफ्ट कौशल की कमी है। 2021 में, ट्रक ड्राइवरों में कौशल की सबसे बड़ी कमी देखी गई, जो पोलैंड की 380 काउंटियों में से 351 में देखी गई।

1.2 श्रम बल की विशेषताएँ

विगत दो दशकों में पोलिश अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और इसका प्रभाव इसकी श्रम शक्ति में दिखाई देता है। बेरोजगारी 2002 के 20.2 प्रतिशत से घटकर अक्टूबर 2021 तक 5.7 प्रतिशत हो गई है। हालांकि, श्रम बल का कुल आकार ज्यादा नहीं बदला है, जो 2004 में 17.27 मिलियन से बढ़कर 2020 में 18.2 मिलियन हो गया है, महिला श्रम बल की भागीदारी पिछले दो दशकों से 48-50 प्रतिशत के बीच स्थिर बनी हुई है। पोलैंड में रोजगार वृद्धि की तीन विशेषताएं चौंकाने वाली हैं। कार्यबल की शैक्षिक योग्यता (तृतीयक शिक्षा के साथ और भी अधिक), श्रम की कमी के कारण अधिक उम्र वाले श्रमिकों (45 और उससे अधिक) के रोजगार में वृद्धि और अस्थायी रोजगार के कारण श्रम बाजार विभाजन (उदाहरण के लिए, अस्थायी कार्य एजेंसियों के माध्यम से निश्चित अनुबंध, और नागरिक कानून अनुबंध) की बढ़ती घटनाएं।

इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स का शोध इस श्रम बाजार विभाजन के संदर्भ में दो चरणों पर प्रकाश डालता है। सबसे पहला, 2002 और 2008 के बीच, पहले से बेरोजगार लोगों की आमद के कारण, अस्थायी रोजगार में 1.7 मिलियन की वृद्धि हुई। दूसरा, 2008 और 2016 के बीच, अस्थायी कर्मचारियों की संख्या में केवल 250,000 की वृद्धि हुई, लेकिन कर्मचारी अपने अस्थायी अनुबंधों में फंसे रहे, जिससे स्थायी नौकरी में स्थानांतरण के अवसर कम हो गए।[30] विगत दो दशकों में, सुधार के दो प्रयासों ने श्रम बाजार को नया आकार दिया है। 2009 में, देश की शीघ्र सेवानिवृत्ति प्रणाली को हटा दिया गया और उसके स्थान पर अधिक प्रतिबंधात्मक ब्रिजिंग पेंशन प्रणाली लागू की गई, जिसमें कर्मचारी वैधानिक सेवानिवृत्ति की

आयु से पांच साल पहले सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुन सकते थे। बाद में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कानून ही निरस्त कर दिया गया।[31]

1.2.1 श्रम बल में प्रवासियों की भूमिका

पोलैंड को काफी पहले से ही उत्प्रवास का देश माना जाता है, विशेषतः यूरोपीय संघ में इसके एकीकरण की वजह से, जब दस लाख से अधिक लोग जर्मनी, नीदरलैंड, यूके, स्पेन और आयरलैंड जैसे पश्चिमी एवं दक्षिणी यूरोपीय देशों में चले गए।[32] हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में, पोलैंड सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि "स्थायी निवास के लिए प्रवासन" में लगातार गिरावट आई है (2006 में 49900 से 2019 में 10,900 तक), खासकर 2015 के बाद से। हालाँकि, पिछले कुछ वर्षों में प्रवासियों की कुल संख्या बढ़ी है। 2002 में, प्रवासी पोलैंड नागरिकों की कुल संख्या 786,100 थी, जो 2011 में बढ़कर 2,017,500 और 2019 में 2,415,000 हो गई। इनमें से अधिकांश युवा (25-40 के बीच) हैं और काम के लिए दूसरे देश जाते हैं।[33] हालाँकि, हाल के वर्षों में, आप्रवासन की बढ़ती दरों के साथ, पोलैंड में कुल प्रवासन दर सकारात्मक (हालाँकि इसमें से कुछ लौटने वाले पोलैंड नागरिकों द्वारा भी प्रेरित है) हो गई है।

पोलैंड में शरणार्थियों एवं आप्रवासियों के प्रति दृष्टिकोण पर 2018 की एक रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि 2014 के बाद, जब श्रम की कमी जाहिर हुई, तो व्यापारिक समुदाय ने श्रम बाजार को खोलने की पैरवी की। परिणामस्वरूप, एक तीन-आयामी रणनीति तैयार की गई - श्रमिकों की मौसमी कमी को दूर करने हेतु 6 पड़ोसी देशों के नागरिकों के लिए परमिट के बिना अस्थायी प्रवास की अनुमति, पोलैंड में अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए रोजगार एवं कामकाजी नियमों को आसान बनाना, और पोल कार्ड (पोलिश मूल के विदेशियों के लिए बनाया गया, जिससे उन्हें पोलैंड में अधिक आसानी से काम करने और पढ़ाई करने की अनुमति मिलती है)।[34] गैर-यूरोपीय देशों से भी आप्रवासन हुआ है, जिसमें वियतनाम, चीन और भारत जैसे देश महत्वपूर्ण हैं।

---

29 PwC (2020), Transport of the Future: Prospects for the Development of Road Transport in Poland in 2020-2030, Retrieved from https:// www.pwc.pl/en/publikacje/2019/transport-of-the-future-prospects-for-the-development-of-road-transport-in-poland-2020-2030.html.

30 Lewandowski, P. & Magda, I. (2018), The labour market in Poland, 2000–2016. IZA World of Labour, Retrieved from: https://wol.iza.org/ articles/the-labor-market-in-poland/long.

31 Ibid.

32 Ibid.

33 Statistics Poland (2020), Demographic situation in Poland up to 2019 International migration of population in 2000–2019.

34 Łaciak, B; Segeš Frelank, J (2018), The Wages of Fear: Attitudes Towards Refugees and Migrants in Poland, Institute of Public Affairs, Retrieved from: https://ec.europa.eu/migrant-integration/node/17011_de.

2019 में, तीसरे देश के नागरिकों (टीसीएन) की आबादी में प्रभुत्व वाले पांच देशों ने निवास परमिट जारी किया - ये देश यूक्रेन (214,700), बेलारूस (25,600), रूस (12,500), वियतनाम (12,100), और भारत (10,000) थे। कुल आप्रवासी आबादी में, शीर्ष 10 देश यूक्रेन (2,106,101), बेलारूस (105,404), जर्मनी (77,073), मोल्दोवा (37,338), रूस (37,030), भारत (33,107), जॉर्जिया (27,917), वियतनाम (27,386), तुर्की (25,049), और चीन (23,838) थे।[35] टीसीएन को जारी किए गए वर्क परमिट 2008 में 18,000 से बढ़कर 2019 में 445,000 हो गए, सीनियर मैनेजमेंट और सलाहकार, शिल्प एवं संबंधित व्यापार श्रमिकों, और संयंत्र एवं मशीन ऑपरेटरों और असेंबलरों जैसे व्यवसायों में 2014-15 के बाद सबसे बड़ी वृद्धि हुई। प्रासंगिकता के अन्य पेशे तकनीशियन और सहयोगी पेशेवर, सेवाएँ एवं बिक्री कर्मचारी, और लिपिकीय सहायता कर्मचारी थे। पोलैंड की अधिकांश विदेशी आबादी मासोवियन वोइवोडीशिप, लेसर पोलैंड, ग्रेटर पोलैंड और लोअर सिलेसिया में केंद्रित है, और अधिकांश पुरुष (संबंधित प्रांत में विदेशी आबादी का 61-77% तक) हैं।[36]

चित्र 4: आप्रवासियों के शीर्ष स्रोत देश

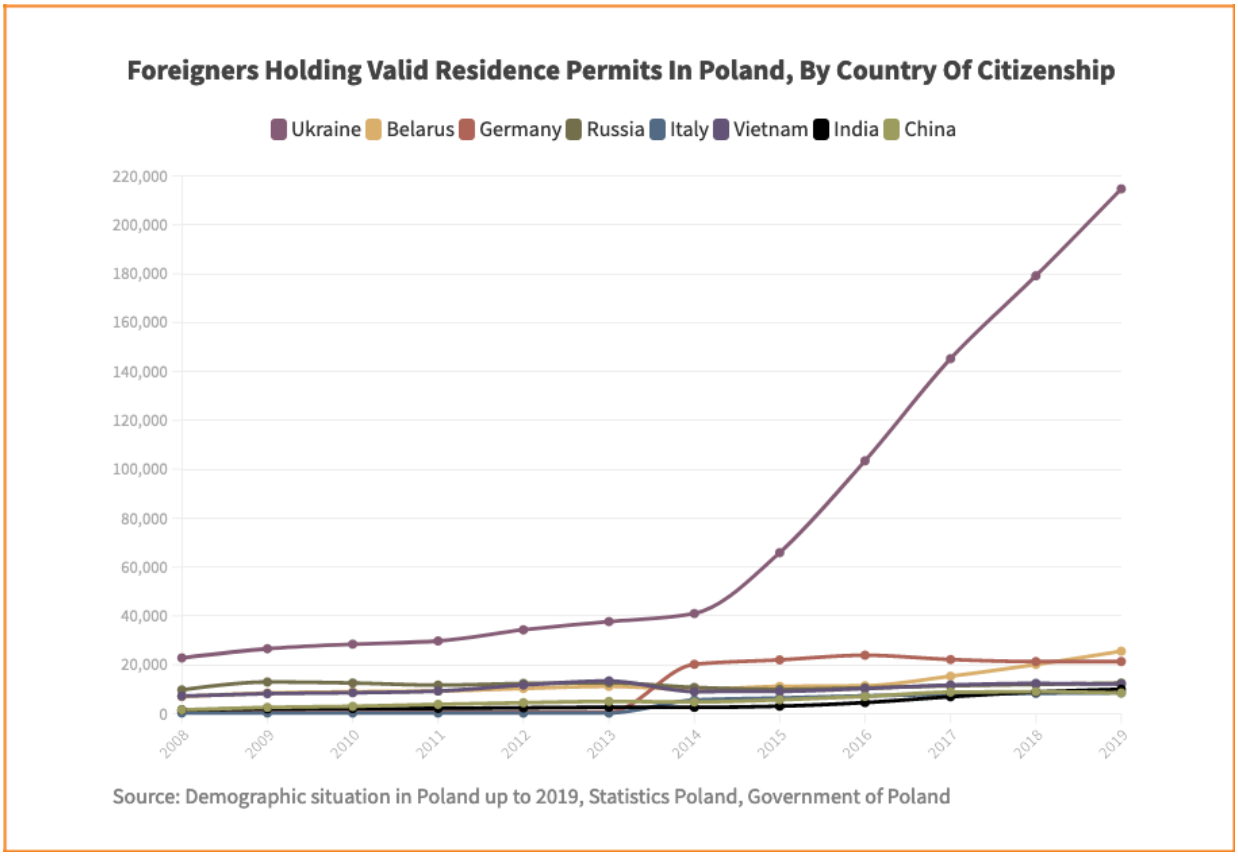

35 Matusz, P & Aivaliotu, E (2020). Circular and temporary migration in Poland during COVID 19. Retrieved from https://admigov.eu/upload/ Deliverable_D32_Matusz_Temporary_and_Circular_Migration_Poland.pdf.

36 Statistics Poland (2020), Demographic situation in Poland up to 2019 International migration of population in 2000–2019.

चित्र 5: एशियाई स्रोत देशों का मानचित्रण

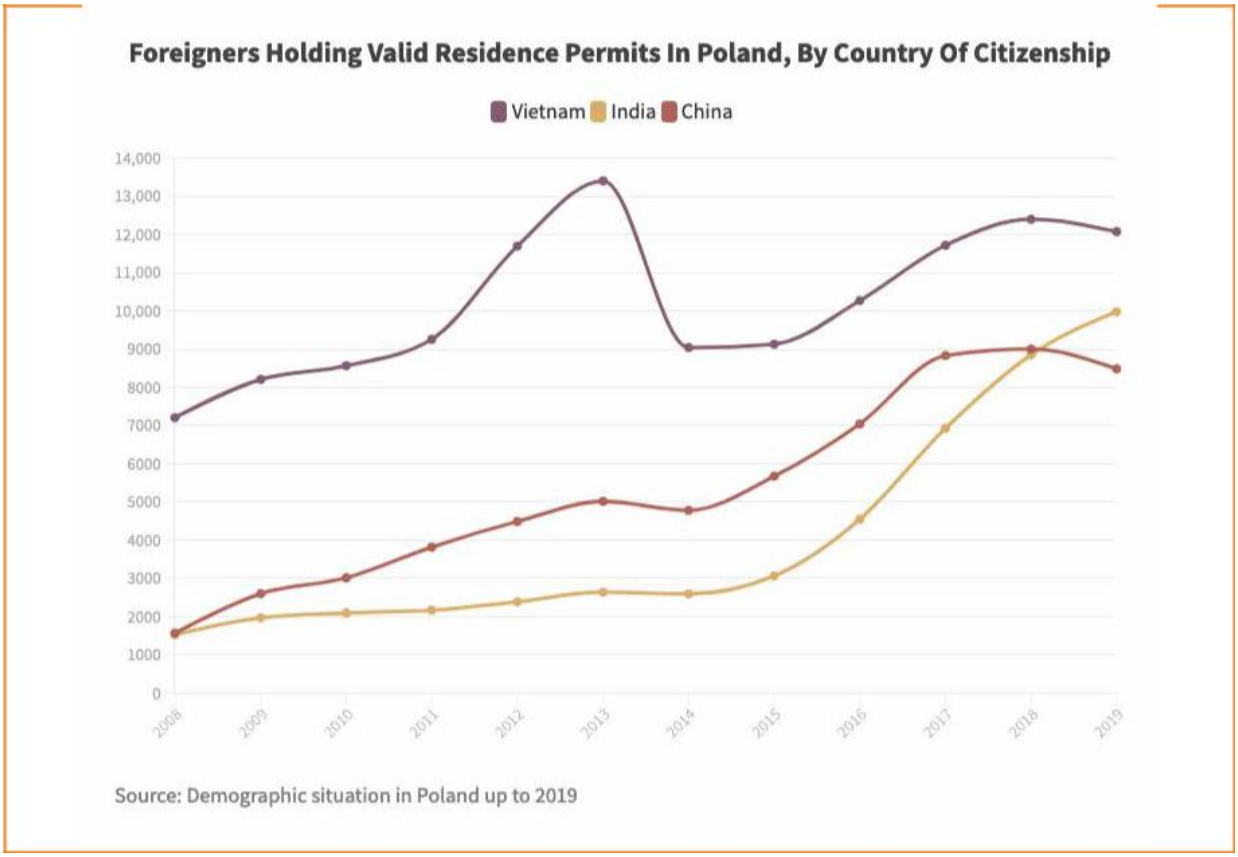

पड़ोसी देश होने के नाते यूक्रेनी प्रवासी पोलैंड में प्रवासी कार्यबल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यूक्रेन और बेलारूस पोलैंड में प्रवासियों के शीर्ष स्रोत देश हैं। पोलिश अर्थव्यवस्था में यूक्रेनी श्रमिक प्रवासियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है, खासकर हाल के वर्षों में।

- 2014 से पहले, पोलैंड में यूक्रेनी प्रवास काफी हद तक अस्थायी था, जो कृषि क्षेत्र एवं देश के पश्चिमी हिस्से से वारसॉ और माज़ोविकी जैसे लोकप्रिय क्षेत्रों तक ही सीमित था।
- 2014 के बाद, जब यूक्रेन में राजनीतिक संकट गहराया, रोजगार हेतु प्रवासन बढ़ा, और पूरे देश से यूक्रेनियन क्राको, ग्दान्स्क, व्रोकला और लॉड्ज़ जैसे पोलिश शहरों की ओर पलायन करने लगे, और निर्माण, आतिथ्य एवं घरेलू काम (महिला) सहित कई क्षेत्रों में काम करने लगे। आप्रवासन की संख्या पर सटीक डेटा की कमी के बावजूद, अध्ययन के ज़रिए अनुमान है कि (कुछ आधिकारिक स्रोतों के आधार पर) 2013-18 के बीच, यूक्रेनी श्रम ने सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में 13 प्रतिशत का योगदान दिया।[37] इस दौरान, यूक्रेनी आप्रवासी आबादी मुख्य रूप से युवा थी, 30-50 वर्ष की आयु के बीच, और उच्च मजदूरी (निर्माण एवं आतिथ्य जैसे क्षेत्रों में),[38] स्थिर राजनीतिक और आर्थिक माहौल और अपने देश से निकटता के कारण पोलैंड की ओर आकर्षित हुए थे।
- फरवरी 2022 के युद्ध के बाद, यूक्रेन से प्रवासन में जबरदस्त वृद्धि हुई है (28 मार्च 2022 तक पोलैंड में 2.3 मिलियन शरणार्थी), जिनमें बड़े पैमाने पर महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं और यह वृद्धि जारी रहेगी। पोलैंड ने शरणार्थियों का पूरे दिल से स्वागत किया है, बिना वीज़ा के प्रवेश की अनुमति दी है और वर्क परमिट संबंधि अनिवार्य को माफ कर दिया है।

37 Strzelecki, P et al (2020), The contribution of immigration from Ukraine to economic growth in Poland, NBP Working Paper No. 322, Re- trieved from https://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/322_en.pdf.

38 Kusek, W. A., (2019), Ukrainian migrants in Poland: Socio-economic inclusion or exclusion? Local Economy, 34(7), 739–744. https://doi. org/10.1177/0269094219889877.

1.3 पोलैंड में भारतीयों का आप्रवासन

पोलैंड में भारतीय आबादी का सांख्यिकीय अनुमान अलग-अलग है, और पोलैंड आंकड़ों के अनुसार, भारतीयों की संख्या अपेक्षाकृत काफी कम है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पोलैंड के निकटतम भौगोलिक देशों, जैसे यूक्रेन, बेलारूस, रूस और जर्मनी के अलावा भारत सबसे प्रासंगिक स्रोत देश है। 2019 में, भारतीयों को 5वीं सबसे अधिक संख्या में निवास परमिट (10,000) मिले, और अप्रवासी समूहों के बीच भारतीयों को जारी किए गए कुल परमिट 6वें सबसे अधिक (33,107) रहे। भारत के विदेश मंत्रालय का 2021 का डेटा पोलैंड में कुल भारतीय आबादी 10,960 (10,162 अनिवासी भारतीय और 798 भारतीय मूल के लोग) की ओर इशारा करता है।[39] यूरोस्टेट डेटा भारत से पोलैंड में प्रवासन पर भी अनुमान देता है। यूरोस्टेट डेटा के अनुसार, 2019 में, पोलैंड ने भारतीयों को दूसरे सबसे अधिक संख्या में ब्लू कार्ड (397) जारी किए, और 2016-19 के बीच देश में भारतीय छात्रों की संख्या 136 प्रतिशत बढ़ गई। पारिश्रमिक के लिए भारतीयों को जारी किए गए कुल परमिट 2012 में 1840 से बढ़कर 2019 में 6532 हो गए, जबकि पहले जारी किए गए परमिट 2012 में 247 से बढ़कर 2019 में 2809 हो गए।[40]

पोलैंड और भारत के बीच प्रेषण पर केवल कुछ डेटा उपलब्ध हैं। हालाँकि, विश्व बैंक डेटा से निर्मित एक सांख्यिकीय मॉडल के आधार पर, प्यू रिसर्च सेंटर ने 2017 में पोलैंड से भारत में 4 मिलियन अमरीकी डॉलर के प्रेषण प्रवाह का अनुमान लगाया। इस डेटा के अनुसार, पोलैंड से प्रेषण बड़े पैमाने पर अन्य यूरोपीय देशों के साथ-साथ चीन, वियतनाम, और नाइजीरिया में भी आता है।[41]

संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन एवं पश्चिमी यूरोप जैसे पारंपरिक गंतव्यों के विपरीत, अपेक्षाकृत बहुत अध्ययनों में ही पूर्वी यूरोप में भारतीय प्रवासियों का अध्ययन किया गया है। पोलिश इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स[42] द्वारा पोलैंड में भारतीय प्रवासियों पर 2014 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पोलैंड की यूरोपीय संघ की सदस्यता से पहले, भारतीय प्रवास की पहली शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी और इसमें बड़े पैमाने पर कपड़ा व्यापारी और सिंधी एवं गुजराती समुदायों के छोटे व्यापारी शामिल थे। 2000 के दशक में, जब यूरोपीय संघ में शामिल होने के दौरान पोलैंड की सीमाओं पर व्यवस्था कड़ी हो गईं, तो कई भारतीय आतिथ्य एवं रेस्तरां जैसे विभिन्न व्यवसायों में लग गए। इसके विपरीत, अन्य लोग पश्चिम यूरोप/संयुक्त राज्य अमेरिका में चले गए। 2015 में किए गए शोध पोलैंड में भारतीयों के तीन मुख्य प्रकारों पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहला, दीर्घकालिक अप्रवासी, उनमें से कुछ उद्यमी। दूसरा, पोलिश कंपनियों के कर्मचारी जो अपने परिवारों के साथ रहते हैं और अंत में, छात्र एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुशल कर्मचारी, जो इंटरकंपनी ट्रांसफर वीज़ा पर हैं जिनका पोलैंड में रहना अस्थायी है।[43] प्रवास की कुछ वजह में शिक्षा, रोजगार, सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता, कैरियर विकास, विवाह, 'प्रवास की संस्कृति' का प्रभाव और नए अनुभवों की तलाश शामिल है।[44] पोलैंड में 40 भारतीयों के साक्षात्कार पर आधारित यह शोधपत्र उद्यमशीलता, थोक व्यापार एवं आतिथ्य (रेस्तरां की स्थापना) के साथ-साथ पोलैंड में बहुराष्ट्रीय कंपनियों/भारतीय निगमों से जुड़ी अस्थायी नौकरी की भूमिकाओं पर प्रकाश डालता है। 2014 की रिपोर्ट में भारतीयों के लिए महत्वपूर्म क्षेत्रों के रूप में थोक व खुदरा व्यापार, आईटी और संचार एवं आतिथ्य पर भी प्रकाश डाला गया है। आईसीटी क्षेत्र और वित्तीय एवं बीमा गतिविधियों में भारतीयों का दबदबा है और वे यूक्रेन के बाद पेशेवर, वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियों में काम करने वाले दूसरे सबसे बड़े देश से हैं।[45] शोध भारतीयों द्वारा सामना किए जाने वाले एकीकरण के मुद्दों पर भी प्रकाश डालता है, जैसे भाषा, भेदभाव के अनुभव (विशेषकर सार्वजनिक जगहों पर), घर की याद आना और अकेलापन। हालाँकि, व्रोकला में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भारतीयों ने प्रवास को व्यक्तिगत

विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना, जबकि महिला प्रवासियों ने इसे आजादी का अनुभव माना।[46] अलग-अलग स्तर पर, अध्ययन इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि कई भारतीयों ने शुरू में पोलैंड को अपनी प्रवास यात्रा में मात्र एक कदम माना, यहां तक कि वे भी जो अभी तक कहीं और नहीं गए हैं।

---

39 MEA, 2021, Retrieved from http://mea.gov.in/images/attach/NRIs-and-PIOs_1.pdf.

40 Data from Eurostat

41 Remittance Flows Worldwide in 2017 (2019), Pew Research Centre, Retrieved from: https://www.pewresearch.org/global/interactives/remit- tance-flows-by-country/.

42 (2014), The Indian Diaspora and Poland-India Relations. Polish Institute for International Affairs. Retrieved from https://www.files.ethz.ch/ isn/185705/The%20Indian%20Diaspora%20and%20Poland–India%20Relations.pdf.

43 Gmaj, K (2019), The Integration of Indians in Poland, Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/332876463_THE_INTEGRA- TION_OF_INDIAN_MIGRANTS_IN_POLAND.

44 Jaskułowski, K. (2017), Indian middling migrants in Wrocław: A study of migration experiences and strategies. Asian and Pacific Migration Journal, 26(2), 262–273. https://doi.org/10.1177/0117196817705777; Gmaj, K (2019), The Integration of Indians in Poland, Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/332876463_THE_INTEGRATION_OF_INDIAN_MIGRANTS_IN_POLAND.

45 (2014), The Indian Diaspora and Poland-India Relations. Polish Institute for International Affairs, Retrieved from https://www.files.ethz.ch/ isn/185705/The%20Indian%20Diaspora%20and%20Poland–India%20Relations.pdf.

46 Jaskułowski, K., (2017), Indian middling migrants in Wrocław: A study of migration experiences and strategies. Asian and Pacific Migration Journal, 26(2), 262–273, https://doi.org/10.1177/0117196817705777.

2 | गतिशीलता मार्ग

2.1 आप्रवासन और वीज़ा नीति

यूरोपीय संघ का सदस्य होने के नाते, पोलैंड ने रिसर्च के ज़रिए यूरोपीय संघ के नागरिकों एवं स्थायी निवासियों, जिन्हें पोलैंड में रहने और काम करने का अधिकार है, और तीसरे देश के नागरिकों (टीसीएन) के बीच अंतर किया है, जिससे पता चलता है कि यूरोपीय संघ के अप्रवासियों को टीसीएन की तुलना में बहुत कम एकीकरण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।[47] सामान्य तौर पर, विदेशियों के आव्रजन, एकीकरण एवं आवागमन को नियंत्रित करने वाले चार कानून हैं - रोजगार संवर्धन एवं श्रम बाजार संस्थान अधिनियम, 2014,[48] विदेशियों पर लागू पोलिश अधिनियम, 2013,[49] 2003 का शरण कानून,[50] एवं नागरिकता कानून, 2009[51]। विदेशियों पर अधिनियम मुख्य रूप से प्रवेश, निकास एवं वीज़ा नीतियों के नियमों से संबंधित है और सभी विदेशियों (विशेषकर जो पोलिश नागरिक नहीं है) पर लागू होता है।

पोलैंड शेंगेन वीज़ा के ज़रिए जाया जा सकता है जो शेंगेन क्षेत्र पर लागू होता है (हालाँकि काम के लिए नहीं) लेकिन इससे लंबे समय तक रहने हेतु राष्ट्रीय वीज़ा भी मिलता है। राष्ट्रीय वीजा, जो आमतौर पर रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा, या परिवार से मिलने/विवाह से संबंधित होता है, को अस्थायी या स्थायी निवास परमिट में बदला जा सकता है, जिसमें पीआर के लिए देश में 5 साल तक लगातार रहना आवश्यक होता है। इस कानून के तहत दिए जाने वाले वर्क परमिट को भी वर्गीकृत किया गया है। इसका आवेदन नियोक्ता - A (पोलिश कंपनियां/पोलैंड में पंजीकृत संस्थाएं), B (बोर्ड सदस्य), C (शाखा कार्यालय/संयंत्र में अस्थायी काम के लिए पोलैंड भेजे गए), D (अस्थायी तदर्थ कार्यों के लिए पोलैंड भेजे गए), और E (A-D के तहत कवर नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए 3 महीने हेतु किसी विदेशी नियोक्ता द्वारा भेजा गया) द्वारा आवेदन किया जाना चाहिए।[52] हालाँकि, कई अतिरिक्त श्रेणियां मौजूद हैं, विशेष रूप से वे जिन्हें वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु वीजा दिया गया है, ब्लू कार्ड धारक और उनके परिवार के सदस्य, और जिन्होंने पोलिश संस्थानों (माध्यमिक विद्यालय और विश्वविद्यालय) में पढ़ाई की है।[53] हालांकि, वर्क परमिट जारी करने हेतु आमतौर पर श्रम बाजार संबंधी जांच आवश्यक होती है (यह प्रमाणित करते हुए कि नियोक्ता उस कार्य हेतु पोलिश या यूरोपीय संघ के नागरिक को ढूंढने में असमर्थ है),

---

47 Renaud (2011), cited in https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/16537/Integration_of_migrants_in_Poland.pdf?sequence=1&isAl- lowed=y.

48 2004, Employment Promotion and Labour Market Institutions Act, Government of Poland, Retrieved from: https://www.paih.gov.pl/files/?id_ plik=7318.

49 ISAP, Retrieved from: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20130001650.

50 2003, Act on on granting protection to aliens within the territory of the Republic of Poland, Government of Poland, Retrieved from: https:// www.asylumlawdatabase.eu/sites/default/files/aldfiles/en%20-%20granting%20protection%20to%20aliens%20within%20the%20territory%20of%20 the%20Republic%20of%20Poland%20.pdf.

51 Poland Citizenship Act 2009, Government of Poland, Retrieved from:

https://www.legislationline.org/download/id/6570/file/Poland_citizen- ship_act_2009_en.pdf.

52 Act of 2013 on Foreigners, Government of Poland, Retrieved from: https://www.refworld.org/docid/54c0b9384.html; Work Permits in Poland. MIGRANTInfo.pl, (IOM & Ministry of Interior, EU), Retrieved from: https://www.migrant.info.pl/Documents_entitling_a_foreigner_to_work_in_ Poland.html.

53 Working in Europe, Euraxess Poland, Retrieved from: https://www.euraxess.pl/poland/information-assistance/work-permit.

इसमें जून 2018 में परिवार, श्रम एवं सामाजिक नीति निदेशालय के एक विनियमन के अनुसार, निर्माण, ट्रक/बस चालक, बुजुर्गों के देखभालकर्ता और स्वास्थ्य देखभाल श्रमिकों जैसे कुछ व्यवसायों को छूट दी गई है।[54]

पोलैंड में एक अन्य कानून भी है जिसमें मोल्दोवा, बेलारूस, जॉर्जिया, रूस, आर्मेनिया और यूक्रेन के नागरिकों को बिना किस अन्य दस्तावेज के 24 महीने[55] तक काम करने की अनुमति (किसी विदेशी को काम सौंपने की घोषणा/ओस्वियाडज़ेनी ओ पॉवियरज़ेनिउ विकोनीवानिया प्रैसी कुडज़ोज़ीमकोवी) दी गई है।[56] ऐसे मामलों में, नियोक्ता को स्थानीय वोइवोडीशिप लेबर ऑफिस में 'किसी विदेशी को काम सौंपने की घोषणा' दाखिल करनी होगी। इसके अलावा, 2015 के श्रम एवं सामाजिक नीति विनियमन मंत्री ने कुछ श्रेणियों के लोगों को परमिट की आवश्यकता से छूट (नर्स, बुजुर्ग देखभाल सहायक, सड़क निर्माण श्रमिक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और भारी ट्रक चालक इनमें से कुछ हैं) दी।[57] विदेशियों पर अधिनियम में जनवरी 2022 के संशोधन[58] में अस्थायी निवास और कार्य परमिट हेतु आवेदन करने वालों के लिए कुछ दस्तावेजों को जमा करने से भी छूट दी गई है - उन्हें अब निवास स्थान एवं स्थिर आय (पूरी की जाने वाली एकमात्र शर्त ~665 यूरो की न्यूनतम आय है) संबंधी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है।

2.2 भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते

प्रवासन और आवागमन पर बहुपक्षीय यूरोपीय संघ-भारत साझा एजेंडा के अलावा, जिसके अंतर्गत पोलैंड आता है, विगत कुछ वर्षों में भारत और पोलैंड के बीच कई आर्थिक क्षेत्रों, यात्रा, रक्षा एलं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर कई द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2007 में पोलिश श्रम मंत्री और भारत के तत्कालीन प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्री के बीच बैठक और कामगारों के आदान-प्रदान पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के साथ-साथ विनियमन हेतु एक संयुक्त कार्य समूह के प्रस्तावित[59] समाचार पत्रों के बावजूद, वर्तमान में, विदेश मंत्रालय के भारत-पोलैंड संबंधों पर फरवरी 2020 के नए दस्तावेज़ के अनुसार, भारत का पोलैंड के साथ प्रवासन और आवागमन पर कोई द्विपक्षीय परिचालन समझौता नहीं है।[60]

वर्ष	द्विपक्षीय समझौते
1956	दूरसंचार विनिमय पर समझौता
1957	सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता
1960	शिपिंग सहयोग पर समझौता
1970	आर्थिक सहयोग पर समझौता
1962	दूसरा आर्थिक सहयोग समझौता
1965	तीसरा आर्थिक सहयोग

54 Regulation of the Family, Labour, and Social Policy Directorate (2018), Retrieved from:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU20180001264/O/D20181264.pdf, cited in Pawlak, M and Koss-Goryszewska, M (2018) Integration of Migrants in Poland: Contradictions and Imaginations.

55 This is likely to increase to 36 months with new proposed legislation, according to the expert interview conducted with the Ministry of Family and Social Policy.

56 Mazovian Voivodeship Office in Warsaw, Government of Poland, Retrieved from: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/nowe-prze- pisy-dotyczace-o-powierzeniu-wykonywania-pracy-cudzoziemcowi.

57 Regulation of the Minister for Labour and Social Policy (April, 2015), Retrieved from: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU20150000588/O/D20150588.pdf : (cited in Pawlak, M and Koss-Goryszewska, M (2018) Integration of Migrants in Poland: Contradictions and Imaginations).

58 Poland: Amended law facilitates the employment of foreigners, European Website on Integration, Retrieved from: https://ec.europa.eu/ migrant-integration/news/poland-amended-law-facilitates-employment-foreigners_en.

59 Indian workers now Poland bound (June,2017), Hindustan Times, Retrieved from: https://www.hindustantimes.com/india/indian-work- ers-now-poland-bound/story-IfpLTmDoIKmyp2D9iF23eO.html.

60 India Poland Relations (February 2020), Ministry of External Affairs, Government of India, Retrieved from: https://www.mea.gov.in/Portal/For- eignRelation/India_Poland_Feb_2020.pdf.

वर्ष	द्विपक्षीय समझौते
1977	हवाई परिवहन पर समझौता
1977	आर्थिक, औद्योगिक एवं तकनीकी सहयोग पर समझौता
1989	आय पर कर के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव और कर चोरी की रोकथाम पर समझौता।
1993	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग पर समझौता।
1996	विदेश कार्यालय परामर्श पर प्रोटोकॉल
1996	निवेश के संवर्धन और संरक्षण पर समझौता
2003	संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने में सहयोग पर समझौता
2003	रक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन
2003	प्रत्यर्पण संधि
2006	आर्थिक सहयोग पर समझौता
2009	स्वास्थ्य देखभाल एवं चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता
2009	पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता
2012	श्रव्य-दृश्य सह-उत्पादन पर समझौता
2013	करों और आय के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम पर समझौते में संशोधन पर प्रोटोकॉल।
2015	राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिए वीज़ा आवश्यकता से छूट पर समझौता
2017	कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहयोग पर समझौता
2019	कोयला खनन के क्षेत्रों में सहयोग

3

कल्याण एवं एकीकरण नीतियां

3.1 राष्ट्रीय स्तर की पहल

अपेक्षाकृत कम समय के कारण पोलैंड में अप्रवासियों की संख्या बढ़ी है, अप्रवासियों को एकीकृत करने हेतु संस्थान और नीतियां धीरे-धीरे विकसित हुई हैं। 2015 से पहले, एकीकरण रणनीति मौजूद ही नहीं थी, यहां तक कि इसे "परित्याग रणनीति" भी कहा गया था।[61] आधिकारिक एकीकरण नीतियां केवल स्वदेश लौटने वालों और 2003 शरण कानून के तहत शरण हेतु आवेदन करने वालों के लिए मौजूद थीं - अंतरराष्ट्रीय संरक्षण के तहत उन लोगों को सामाजिक सहायता पर 2004 अधिनियम में निर्धारित एकीकरण लाभ मिलते हैं। शरणार्थी का दर्जा पाने वालों के लिए 2000 में व्यक्तिगत एकीकरण कार्यक्रम (आईपीआई) की शुरूआत राज्य की नीति के पहले साधनों में से एक थी और यह पोलैंड में एकीकरण नीति की संकल्पना का एक आधार बन गया है।[62] एकीकरण वर्तमान में सामाजिक सहायता एवं एकीकरण विभाग, परिवार और सामाजिक नीति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो विदेशियों के एकीकरण पर एक अंतर-मंत्रालयी कार्य समूह का समन्वय करता है।[63] जुलाई 2012 में, एकीकरण पर पहला रणनीति दस्तावेज़, जिसे 'पोलिश प्रवासन रणनीति - वर्तमान स्थिति और प्रस्तावित कार्रवाइयां' कहा जाता है, का मसौदा तैयार किया गया था। इस दस्तावेज़ के अनुसार, एकीकरण नीति राष्ट्रीय सरकार द्वारा स्थापित की जानी थी, स्थानीय सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जानी थी, और श्रमिक आप्रवासियों के आर्थिक एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोपीय संघ के धन के समर्थन से स्थापित की जानी थी। हालाँकि, 2015 के शरणार्थी संकट के मद्देनजर इसपर कभी काम नहीं हो सका।[64]

2015 के बाद: 2015 के शरणार्थी संकट के कारण, जिससे यूरोपीय संघ एवं यूक्रेन संकट की वजह से शरण के लिए आवेदनों में अधिक वृद्धि की, पोलैंड में जनता की राय प्रवासन के प्रति सचेत हो गई। 2019 में, आंतरिक एवं प्रशासन मंत्रालय ने एक पोलिश प्रवासन नीति तैयार की, जिसे अभी अपनाया जाना बाकी है। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं:

- स्थायी निवास हेतु आवेदन करने के लिए **एकीकरण** कार्यक्रम को उत्तीर्ण करना, 'एकीकरण' को "पोलिश समाज में व्यक्ति की सबसे बड़ी संभव स्वतंत्रता, पोलैंड में किसी विदेशी के रहने से संबंधित खर्च को कम करना और जो संभावित समायोजन की एक आवश्यक शर्त है" के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें पोलिश भाषा जैसे व्यावहारिक ज्ञान एवं पोलिश धर्म (कैथोलिक धर्म) और समाज के नैतिकता और मूल्यों के अनुसार रहना शामिल है।

---

61 D. Szelewa, Model integracji społecznej imigrantów z krajów trzecich: dostęp do usług społecznych i przegląd polityki społecznej, Raporty i Analizy, Warsaw 2010, p. 29,

62 Rajca, L., (2021), The Evolution of the Approach to the Integration of Immigrants in Poland. Studies in European Affairs. 25(3), 10.33067/ SE.3.2021.5.

63 Governance of Migrant Integration in Poland, DG For Migration & Home Affairs, European Union, Retrieved from: https://ec.europa.eu/ migrant-integration/country-governance/governance/poland_en.

64 Rajca, L. (2021), The Evolution of the Approach to the Integration of Immigrants in Poland. Studies in European Affairs. 25(3), 10.33067/ SE.3.2021.5.

- नागरिकता हेतु आवेदन करने के लिए **समायोजन** कार्यक्रम को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना - 'समायोजन' को "पोलैंड में बाध्यकारी मूल्यों को समझना और पहचानना एवं पोलैंड में सामाजिक एकजुटता और सुरक्षा हेतु खतरा पैदा करने वाले मूल्यों को अस्वीकार करना" के रूप में परिभाषित किया गया है।

हालाँकि यह अभी तक कानून नहीं है, फिर भी इस नीति की कई लोगों ने आलोचना की है। हेलसिंकी फाउंडेशन फॉर ह्यूमन राइट्स और कमेटी फॉर माइग्रेशन रिसर्च (पोलिश एकेडमी ऑफ साइंसेज) जैसे संगठनों के बयान इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि यह नीति सुरक्षा जोखिम के रूप में प्रवासन की ऐसी धारणा पर आधारित है जो पोलैंड में विभिन्न प्रकार के आप्रवासन की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करती है और बहुसंस्कृतिवाद के लिए जिम्मेदार नहीं है।[65]

एकीकरण नीति अप्रवासी के जीवन के लगभग हर पहलू में प्रासंगिक है, जिसमें श्रम बाजार, शिक्षा, राजनीतिक भागीदारी, स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच एवं भेदभाव-रोधी शामिल हैं। दुनिया भर के विभिन्न देशों में आप्रवासी एकीकरण नीति की सीमा को मापने वाले प्रवासी एकीकरण नीति सूचकांक में पोलैंड का स्कोर, समय के साथ इसकी एकीकरण चुनौतियों के विकास पर प्रकाश डालता है। वर्तमान में, पोलैंड का श्रम बाजार की गतिशीलता, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं राजनीतिक भागीदारी में औसत से कम स्कोर के साथ एमआईपीईएक्स पर 40/100 का स्कोर है। पोलैंड इस स्कोर की वजह से "मात्र कागज पर समानता" माने जाने वाले एकीकृत दृष्टिकोण वाले देशों के समूह में है - ऐसे देश जो आंशिक रूप से बुनियादी अधिकार और सुरक्षा प्रदान करते हैं लेकिन ऐसी कोई समान अवसर और नीतियां नहीं हैं जो अप्रवासियों के प्रति प्रतिकूल दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करती हों।[66] राष्ट्रीय स्तर की एकीकरण नीति की कमी के

बावजूद, प्रवासन पृष्ठभूमि वाले लोगों को कुछ कानूनों जैसे शिक्षा कानून पर अधिनियम, सार्वजनिक निधि द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं पर अधिनियम और सामाजिक सहायता पर अधिनियम में आंशिक रूप से शामिल किया गया है।[67] प्रवासन पृष्ठभूमि वाले कानूनी रूप से निवासी बच्चों को प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों पर शिक्षा तक पहुंच की गारंटी दी जाती है। बच्चों को एकीकृत करने में मदद करने के लिए अतिरिक्त उपाय, जैसे पोलिश भाषा कक्षाएं, प्रारंभिक पाठ्यक्रम और प्रवासी भाषा में प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, हाल ही में किए गए उपाय हैं।[68]

3.2 स्थानीय स्तर की पहल

पोलैंड के प्रमुख शहरों में राष्ट्रीय स्तर की एकीकरण रणनीतियों एवं स्थानीय एवं शहर-स्तरीय एकीकरण पहल की आवश्यकता देखी गई है। 2017 में, वारसॉ, ग्दान्स्क, व्रोकला और क्राको सहित 12 शहरों ने आप्रवासी एकीकरण के लिए सहयोग पर एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए। एक दूसरी घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे "मैत्रीपूर्ण एवं सुरक्षित" पोमेरेनियन प्रांत का निर्माण हुआ।[69]

- **वारसॉ** शहर, जहां सबसे अधिक आप्रवासी आबादी है, में शहर प्रशासन द्वारा समर्थित एक पहल और यूरोपीय संघ के वित्त पोषण के साथ एनजीओ संघ द्वारा संचालित बहुसांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई। यह केंद्र निवास परमिट, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय और एकीकरण पहल जैसे पोलिश भाषा पाठ्यक्रम, सूचना एवं परामर्श, सामाजिक एकजुटता और बहुसांस्कृतिक पहल के लिए कम अनुदान पर कानूनी सलाह प्रदान करता है। यह शहर में अप्रवासी समुदायों के लिए सामाजिक मिलन स्थल का कार्य करता है।[70] नवंबर 2012 में, शहर ने विदेशियों के लिए सामाजिक संवाद समिति की भी स्थापना की, जिसमें विदेशियों एवं विदेशी संघों के साथ काम करने वाले 18 गैर सरकारी संगठन शामिल थे।[71] नवंबर 2012 में, शहर में विदेशियों के लिए सामाजिक संवाद समिति की भी स्थापना की गई, जिसमें विदेशियों और विदेशी संघों के साथ काम करने वाले 18 गैर सरकारी संगठन शामिल थे।

65 Committee for Migration Research (2019), Retrieved from: http://www.kbnm.pan.pl/images/Stanowisko_KBnM_Polska_polityka_migracyj- na_03072019.pdf; Helsinki Foundation for Human Rights (2019), Retrieved from: https://www.hfhr.pl/politykamigracyjnapolski/.

66 MIPEX 2020, Migration Policy Group, Retrieved from: https://www.mipex.eu/key-findings.

67 Kosz-Goryszewska, M., & Pawlak, M. (2018), Integration of migrants in Poland: Contradictions and imaginations in Kucharczyk, J & Mesežnikov, G (ed) Phantom Menace. The Politics and Policies of Migration in Central Europe. Institute for Public Affairs & Heinrich-Böll-Stiftung. Retrieved from: https://cz.boell.org/en/2019/02/14/phantom-menace.

68 Ibid.

69 (2012), Poland: The biggest cities speak with one voice on immigrant integration, European Website on Integration, Retrieved from: https:// ec.europa.eu/migrant-integration/news/poland-biggest-cities-speak-one-voice-immigrant-integration_en

70 The Warsaw Multicultural Centre, Retrieved from: https://centrumwielokulturowe.waw.pl/en_gb/en/

71 (2012), Poland: The Social Dialogue Committee for Foreigners has just been established in Warsaw, Retrieved from: https://ec.europa.eu/ migrant-integration/news/poland-social-dialogue-committee-foreigners-has-just-been-established-warsaw_en

- **ग्दान्स्क** अच्छे आप्रवासी एकीकरण मॉडल वाला एक और शहर है,[72] जिसने इसके लिए 2018 इनोवेशन इन पॉलिटिक्स पुरस्कार जीता है। 2015 में, शहर प्रशासन ने आप्रवासी एकीकरण पर पोलैंड की पहली क्रॉस-सेक्टोरल और अंतःविषय टास्क फोर्स की स्थापना की, जो आप्रवासी जरूरतों

एवं खामियों की पहचान करने पर काम करने वाले 70 सार्वजनिक संस्थानों एवं गैर सरकारी संगठनों से 150 सदस्यीय निकाय से बनाई गई है। टास्क फोर्स ने 8 विषयगत समूहों (शिक्षा, संस्कृति, आवास, सामाजिक सहायता, रोजगार, हिंसा, स्थानीय समुदाय और स्वास्थ्य) के माध्यम से काम किया और इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में चुनौतियों को चिन्हित किया। इनमें से कुछ शामिल हैं:

- शहर में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए सूचना, परामर्श एवं भाषा समर्थन की कमी है।
- अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पोलिश रीति-रिवाजों से अनभिज्ञता एवं पोलिश साथियों से अलगाव।
- भाषा संबंधी बाधाएं और स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को समझने की आवश्यकता।
- विदेशी के रूप में देश के नागरिकों से बातचीत करते समय कमजोरियाँ।
- सामुदायिक स्तर पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आपसी समझ का अभाव।
- ख़राब कामकाजी परिस्थितियाँ, नस्लवाद, भेदभाव।

कार्य समूह के निष्कर्षों के आधार पर, ग्दान्स्क शहर प्रशासन ने 2023 तक आप्रवासी एकीकरण के लक्ष्यों को हासिल करने हेतु प्रतिबद्धता दर्शाई है। योजनाबद्ध विशिष्ट पहलों में सिटी हॉल में आप्रवासी सर्विस काउंटर, शहर के सभी आप्रवासियों के लिए आप्रवासी सूचना एवं सहायता केंद्र, जहां वे निवास, कैरियर मार्गदर्शन, भाषा समर्थन, आवास सहायता पर सलाह ले सकते हैं, नए आप्रवासियों के लिए एक सूचना संसाधन के रूप में ग्दान्स्क सिटी स्टार्टर पैक, नए अप्रवासियों को वित्तीय सहायता, व्याख्या/अनुवाद सेवाओं के साथ पोलिश भाषा पाठ्यक्रम, नगर निगम भेदभाव रोधी टीमें, आप्रवासी मुद्दों को नगर प्रशासन तक पहुँचाने के लिए आप्रवासी परिषद, अंतरधार्मिक संवाद के लिए परिषद, और ग्दान्स्क विश्वविद्यालय में एक प्रवासन और बहुसंस्कृतिवाद अनुसंधान केंद्र की स्थापना शामिल है।

- व्रोकला अप्रवासियों के लिए शहर-स्तरीय एकीकरण उपाय शुरु करने वाला पोलैंड का एक अन्य शहर है। व्रोकला सेंटर फॉर सोशल डेवलपमेंट द्वारा विलोकुल्टुरोवी व्रोकला परियोजना बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने और व्रोकला 2018-22 में अंतरसांस्कृतिक संवाद की रणनीति के हिस्से के रूप में विभिन्न समुदायों के अप्रवासियों का समर्थन करने हेतु इस शहर की पहल है। इस संवाद का उद्देश्य पांच विषयगत क्षेत्रों में लक्ष्यों को तय करना है, जिसमें शिक्षा, आप्रवासियों का एकीकरण, सुरक्षा और कानून के ज्ञान को बढ़ावा देना, और सहयोग और अंतरसांस्कृतिक संचार शामिल है।[73] मौजूदा पहलों में व्रोमिग्रांट प्रोग्राम[74] भी शामिल है जो शहर में अप्रवासियों के लिए यूक्रेनी, रूसी, जर्मन एवं अंग्रेजी में उपलब्ध एक मुफ्त सूचना और परामर्श संसाधन है।

72 Immigrant Integration Model (2016), Gdansk City Hall, Retrieved from: https://download.cloudgdansk.pl/gdansk-pl/d/20170691579/immi- grant-integration-model.pdf

73 Strategy for Intercultural Dialogue in Wroclaw 2018-22, Municipality of Wroclaw, Retrieved from: https://www.wielokultury.wroclaw.pl/ wp-content/uploads/the_strategy_for_the_intercultural_dialogue_in_wroclaw.pdf

74 WroMigrant. Information and activity points for migrants, Retrieved from: https://www.wielokultury.wroclaw.pl/en/wromigrant-en/

4 | कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट की कार्यप्रणाली पोलैंड में श्रम बाजार के बारे में डेटा, अध्ययन, रिपोर्ट एवं नीति दस्तावेजों की प्रारंभिक माध्यमिक समीक्षा पर निर्भर करती है। चुने गए देशों के श्रम बाजार एवं प्रवासन गलियारे की क्षमता का आकलन करने हेतु निम्नलिखित मानदंडों का उपयोग किया जाएगा:

1. **चयनित देशों में मांग पक्ष का विश्लेषण:** राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर गंतव्य देश में आर्थिक प्रोफ़ाइल, जनसांख्यिकीय विशेषताएं, श्रम बल की विशेषताएं, कौशल की कमी और अधिशेष। यह खंड चयनित देश की अर्थव्यवस्था और श्रम बल की प्रमुख विशेषताओं पर भी केंद्रित रहेगा, जिसमें प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, शुद्ध प्रवासन दर और प्रेषण का आगमन/बहिर्वाह शामिल है।
2. **गंतव्य देश में मौजूदा भारतीय जनसंख्या:** गंतव्य देशों में मौजूदा भारतीय जनसंख्या का आकार और विशेषताएं - जिसमें छात्रों, श्रमिकों, परिवार के आश्रितों की संख्या, निवास और जारी किए गए ब्लू कार्ड की संख्या, शैक्षिक, पारिवारिक और पारिश्रमिक गतिविधियों के लिए परमिट और वर्षों में भारतीयों के आप्रवासन में समग्र रुझान शामिल हैं।
3. **आवश्यक कौशल का आपूर्ति पक्ष का विश्लेषण:** चयनित देश में सेवा योग्य श्रम की कमी को समझने के लिए क्षेत्र के हित में भारत की कौशल प्रोफ़ाइल और क्षमताओं के साथ अनुमानित मांग पक्ष की कमी का मानचित्रण करना।
4. **नीति परिदृश्य:** द्विपक्षीय एवं एकतरफा नीति इकोसिस्टम जो भारत और चयनित देशों के बीच प्रवास को नियंत्रित करता है - इसमें ईसी निर्देश, देशों में राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर के कानून, प्रवेश-निकास कानून, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और एकीकरण नीतियां, क्षेत्रीय नीतियां, छात्र प्रवासियों के लिए वर्क परमिट नीतियां शामिल हैं। भारत के साथ द्विपक्षीय समझौते (श्रम गतिशीलता भागीदारी एवं सामाजिक सुरक्षा समझौते) के साथ-साथ भारत के वर्तमान उत्प्रवास ढांचे, और भारत में राज्य स्तर पर नीतियां। यह खंड गंतव्य देशों में कल्याण प्रणालियों और चयनित देशों में प्रवासियों के लिए भाषा प्रशिक्षण और ऑन-साइट प्रशिक्षण जैसी अपस्किलिंग पहल की उपलब्धता पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।
5. **एकीकरण क्षमता:** सामान्य रूप से श्रमिक आप्रवासियों और भारत से आए लोगों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम और नीतियां।

यह रिपोर्ट विभिन्न दृष्टिकोणों से प्रमुख श्रमिक प्रवासन समस्याओं का पता लगाने, ज्ञान में अंतराल को दूर करने और भारत के साथ पोलैंड के प्रवासन गलियारे को समझने के लिए प्रमुख सूचनार्थ साक्षात्कारों में हितधारक परामर्श का भी उपयोग करती है। विभिन्न हितधारकों के लिए प्रश्नावली का मसौदा साहित्य समीक्षा के प्रारंभिक निष्कर्षों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें कौशल की कमी, श्रम बाजार की स्थिति और आव्रजन एवं प्रवासी एकीकरण पर संस्थागत ढांचे शामिल हैं। हितधारक परामर्श में भारतीय प्रवासी के सदस्यों के साथ साक्षात्कार भी शामिल थे। रिपोर्ट का अगला भाग पोलिश एवं भारतीय हितधारकों के साथ आयोजित हितधारक परामर्श के निष्कर्षों का विवरण देता है।

5 | मुख्य सूचनार्थी साक्षात्कार निष्कर्ष

5.1 पोलैंड में श्रम बाज़ार के अवसर

इस खंड में, हम पोलैंड में श्रम बाजार के अवसरों पर उत्तरदाताओं के विचारों का अध्ययन करेंगे, जिसमें देश की आर्थिक वृद्धि, कमी की अंतर-क्षेत्रीय प्रकृति, भर्ती की रणनीतियों एवं आव्रजन नीति की भूमिका शामिल है। इस खंड में विभिन्न प्रवासी देशों, एशियाई आप्रवासियों की बढ़ती प्रोफ़ाइल और विशेषतः भारतीय आप्रवासियों पर भी चर्चा की गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, इस खंड में, सरकार का तात्पर्य पोलैंड की सरकार से है।

5.1.1 बढ़ती अर्थव्यवस्था, अंतर-क्षेत्रीय कमी

बढ़ती अर्थव्यवस्था, श्रम की कमी एक बढ़ती बाधा: हर एक श्रेणी के हितधारकों के उत्तरदाताओं ने पोलिश अर्थव्यवस्था की बढ़ती प्रकृति एवं सभी क्षेत्रों में नौकरी की रिक्तियों और कमी में सहवर्ती वृद्धि पर प्रकाश डाला। एक प्रमुख अनुसंधान संगठन[75] के एक प्रतिनिधि ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पोलैंड की आबादी उम्मीद से कहीं अधिक तेजी से बूढ़ी हो रही है, और श्रम बाजार में फ्लो आवश्यका के स्तर का नहीं है। उनके अनुसार, देश के अनुमानित 2-2.5 मिलियन आप्रवासी बड़े पैमाने पर श्रमिक प्रवासी हैं और अल्प बेरोजगारी दर का अनुभव करते हैं। अनुसंधान संगठनों और सरकार सहित कई हितधारकों ने पोलिश प्रवासन के संबंधी तथ्यों को दोहराया, कि देश, हाल तक, उत्प्रवास में से एक था और अभी भी एक बढ़ती वास्तविकता के रूप में आप्रवासन को अपनाने की प्रक्रिया में है। सरकारी प्रतिनिधियों[76] ने बताया कि पोलैंड में बेरोजगारी दर भी पहले से काफी निचले स्तर पर है, जो आगे श्रम बाजार की कमी को पूरा करने हेतु आप्रवासन की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है और यह कमी निम्न और उच्च कौशल वाले पदों में है। आप्रवासन भी बढ़ रहा है, विशेष रूप से पिछले 4 वर्षों में और कोविड-19 महामारी के दौरान, जिसकी सबसे बड़ी वजह श्रम बाजार की कमी, प्रतिकूल जनसांख्यिकीय स्थितियों एवं उच्च प्रवासन है। बहुपक्षीय संगठन[77] के एक प्रतिनिधि ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पोलैंड में 50 प्रतिशत से अधिक नियोक्ता श्रम की कमी की बात कहते हैं, जो अब विकास एवं व्यवसाय विकास में बाधा बन रहा है। एक शोध संगठन[78] के उत्तरदाता ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में जर्मनी के साथ एक दिलचस्प आर्थिक समानता की बात कही, जिसमें बताया गया कि 1950 के दशक में जर्मनी की तरह, पोलैंड को भी आज देश की आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने हेतु एक बड़ी, सस्ती श्रम शक्ति की आवश्यकता है। अल्पकालिक नीति दृष्टिकोण, जो आज की कमी पर केंद्रित है, में कई आप्रवासियों की बढ़ती सामाजिक गतिशीलता और करियर आकांक्षाओं पर विचार नहीं किया गया है, जिससे भविष्य में एकीकरण की चुनौतियाँ पैदा हो सकती हैं।

---

75 Interview Code IOM/2

76 Interview Code IOM/1

77 Interview Code IOM/7

78 Interview Code IOM/6

अभिरुचि के प्रमुख क्षेत्र : साक्षात्कार में श्रमिकों की कमी का सामना करने वाले कई क्षेत्रों और उद्योगों का नाम सामने आया। कृषि को कमी वाले शुरुआती क्षेत्रों में से एक माना गया था और परिणामस्वरूप, अप्रवासी श्रम शक्ति की भी कमी थी। एक शोध संस्थान के उत्तरदाता के अनुसार, अब यह कमी निर्माण, आतिथ्य, होटल सेवाओं, देखभाल एवं सफाई सेवा जैसे क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है। कृषि, देखभाल और निर्माण को अब प्रवासी-श्रमिक क्षेत्रों का लेबल दे दिया गया है, जो विगत कुछ वर्षों में एक बुनियादी संरचनात्मक परिवर्तन है। इन क्षेत्रों में नियोक्ताओं को आवश्यक श्रम बल की भर्ती में चुनौतियों का

सामना करना पड़ता है।[79] एक विशेषज्ञ के अनुसार, बढ़ता खाद्य वितरण क्षेत्र (उबेरईट्स, बोल्ट) भी आवश्यक है, खासकर छात्रों के लिए, जिनमें से कई ऐसे पदों पर अंशकालिक काम करते हैं। बहुपक्षीय संगठन[80] के एक प्रतिनिधि ने व्यापार क्षेत्र (विशेष रूप से शहरों में गतिशील रूप से बढ़ रहा है), परिवहन एवं रसद (विशेष रूप से महामारी के दौरान), और निर्माण पर प्रकाश डाला। व्यवसाय में, उच्च कौशल वाले पदों के लिए आमतौर पर पोलिश नागरिक की आवश्यकता नहीं होती है। हालाँकि, अन्य दो में ज्यादातर कम कौशल वाले श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है और उन्हें भाषा कौशल की आवश्यकता होती है। सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासनिक सेवाओं, गोदाम प्रबंधन, परिवहन और रसद जैसे क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया कि ये कोविड-19 महामारी से अधिक प्रभावित नहीं हुए। कई सरकारी प्रतिनिधियों के अनुसार, निर्माण, कृषि, परिवहन एवं प्रसंस्करण उद्योग जैसे क्षेत्र कम कौशल वाले पदों के लिए उपयुक्त हैं और आईटी व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र उच्च कौशल वाले पदों के लिए प्रासंगिक हैं।[81] हालाँकि, सरकारी प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पोलैंड आप्रवासन के साथ श्रम बाजार की जरूरतों को संतुलित करना चाहता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश में सामाजिक एकजुटता प्रभावित न हो।[82] सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि 2018-2021 के बीच, विदेशी श्रमिकों को मुख्य रूप से औद्योगिक प्रसंस्करण, निर्माण, प्रशासन सेवाओं एवं सहायक गतिविधियों, परिवहन और गोदाम प्रबंधन में काम पर रखा गया था। हालाँकि उच्च कौशल वाले पेशेवर अभी आप्रवासी श्रमिकों का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा (विभिन्न प्रकार के परमिटों में 1-3% के बीच) हैं, 2021 में ऐसे काम के लिए रिकॉर्ड संख्या में परमिट (~ 15,000) जारी किए गए थे, मुख्य रूप से आईटी, आर्थिक विशेषज्ञ और प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए। हालाँकि, यह भी बताया गया कि कई लोग आधिकारिक तौर पर स्टाफिंग/भर्ती फर्मों में कार्यरत हैं और अपनी सेवाओं के लिए ग्राहकों को काम पर रखते हैं। इसलिए आधिकारिक आंकड़ों से उनकी सटीक कार्य भूमिका का पता नहीं चलता है। नियोक्ता महासंघ[83] के एक प्रतिनिधि ने कहा कि हालांकि आईटी एवं उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उर्ध्वगामी गतिशीलता और अपस्किलिंग होती है, लेकिन निर्माण जैसे क्षेत्रों में यह सामान्य नहीं है।

बिचौलियों और निजी कंपनियों की महत्वपूर्ण भूमिका: श्रमिक आव्रजन में भर्ती एजेंसियों एवं निजी क्षेत्र द्वारा निभाई गई भूमिका का उल्लेख कई हितधारकों ने किया था, जिन्होंने बताया कि यह श्रम की कमी के साथ धीमी गति से चलने वाली आव्रजन नौकरशाही के कारण है। सरकारी उत्तरदाताओं[84] ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुछ क्षेत्रों में श्रम बाजार जांच होती है, जैसे कि किसी विदेशी कर्मचारी को काम पर रखने से पहले नियोक्ता को यह मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है कि किसी पद हेतु योग्य है या नहीं। अनुसंधान संस्थानों और बहुपक्षीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने पोलैंड के प्रवासन इकोसिस्टम को आकार देने में भर्ती एजेंसियों द्वारा निभाई जाने वाली प्रमुख मध्यस्थ भूमिका की ओर इशारा किया। जटिल कागजी कार्रवाई के बोझ को प्रबंधित करने हेतु ऐसे मध्यस्थ विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। बहुपक्षीय संगठन[85] के एक प्रतिनिधि ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि विदेशी भर्ती के लिए दबाव मुख्य रूप से व्यावसायिक हितों और निजी क्षेत्र से है। एक नियोक्ता महासंघ के एक प्रतिनिधि ने कहा कि कोविड से पहले, नियोक्ता श्रम की कमी और विदेशी श्रमिकों के मुद्दे पर सरकार पर दबाव डाल रहे थे। उन्होंने कहा कि कई नियोक्ता विदेशी श्रमिकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने हेतु खर्च उठाने को तैयार हैं और इसपर सहयोग करना चाहते हैं। हालाँकि, वे प्रवासन नीति से संबंधित स्पष्टता की कमी के कारण मजबूर हैं, जो आप्रवासन के प्रति सार्वजनिक धारणा से प्रभावित है।

---

79 Interview Code IOM/2

80 Interview Code IOM/7

81 Interview Code IOM/9, IOM/10

82 Interview Code IOM/10

83 Interview Code IOM/13

84 Interview Code IOM/9

85 Interview Code IOM/5

5.1.2 पड़ोसी देशों का प्रभुत्व, उभरते एशियाई गलियारे

यूक्रेन और अन्य पड़ोसी देश: उत्तरदाताओं से मौजूदा समय में महत्वपूर्ण देशों के बारे में पूछा गया। लगभग हर एक ने बेलारूस, मोल्दोवा और, सबसे महत्वपूर्ण, यूक्रेन जैसे पड़ोसी देशों की भूमिका महत्वपूर्ण बताई। जैसा कि रिपोर्ट में पाया गया है, यूक्रेन पोलैंड[86] में आप्रवासन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है और श्रम बल के लिए महत्वपूर्ण है। 2014 में युद्ध के मद्देनजर यूक्रेन से आप्रवासन काफी बढ़ गया। हालांकि एक शोध संस्थान[87] के एक प्रतिनिधि ने कहा कि यूक्रेन की श्रम कमी की गंभीर स्थिति और पश्चिमी यूरोपीय की अपील के कारण कुछ समय में यह श्रम बल कम हो जाएगा। यूक्रेनी प्रवासियों के लिए जर्मनी जैसे देशों में फरवरी 2022 के संघर्ष के कारण स्थिति में काफी बदलाव आया है। पहले के आंकड़ों से पता चलता है कि घोषणाओं में यूक्रेन की हिस्सेदारी[88] 2018 में 91 प्रतिशत से गिरकर 2021 में 83 प्रतिशत हो गई, और वर्क परमिट के लिए, सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2018 में 73 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 64 प्रतिशत हो गया। हालाँकि, 28 मार्च 2022 तक, पोलैंड में अभी 23 लाख यूक्रेनी शरणार्थी, लेकिन युद्ध जारी रहने के कारण यह संख्या और बढ़ने की संभावना है।[89]

पोलैंड में निजी क्षेत्र महासंघ[90] के एक भारतीय प्रतिनिधि का मानना था कि मौजूदा संकट श्रम बाजार एवं आप्रवासन में नाटकीय बदलाव लाएगा और पोलैंड के कहीं और से आप्रवासन को प्रोत्साहित करने की संभावना नहीं है। अधिकांश शरणार्थी पुरुषों की बजाय महिलाएं और बच्चे हैं। उनके अनुसार, संभावना है कि शरणार्थी सफेदपोश नौकरियों और खाद्य प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग जैसे उद्योगों में मांग को पूरा कर सकेंगे। उत्तरदाता का कहना था कि पोलैंड युद्ध की वजह से पहले ही श्रम की भारी कमी का सामना कर रहा था, इसके बावजूद बड़ी संख्या में शरणार्थी आ गए हैं, सरकार को उन सभी को रोजगार और सहायता देने में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यूक्रेनी शरणार्थियों के प्रति पोलैंड की "खुले दरवाजे" की नीति पर प्रकाश डाला है, जिसमें सरकार ने वीजा एवं वर्क परमिट आवश्यकताओं को माफ कर दिया है। महासंघ के प्रतिनिधि ने भी पोलैंड में यूक्रेनियनों को लाभान्वित करने वाली सांस्कृतिक और भाषाई समानता पर रिपोर्ट में पाए गए समान विचार व्यक्ति किए। हालाँकि, अभी भी इस सवाल का जवाब तलाशने की आवश्यकता है कि क्या नई यूक्रेनी श्रम शक्ति पोलैंड में वर्तमान में मौजूद श्रम की विशेष कमी को पूरा कर सकेगी। वारसॉ में एक शरणार्थी-केंद्रित कल्याण केंद्र[91] के साथ काम करने वाले एक उत्तरदाता ने कहा कि पूर्व में यूक्रेनियन सेवा एवं विनिर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं और कम वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालाँकि यूक्रेनियन अब पोलैंड में श्रम की कुछ कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि स्वास्थ्य सेवा, रसद आदि जैसे क्षेत्रों में अधिक कमी को इस श्रम बल द्वारा संबोधित किया जा सकता है या नहीं।

एक अन्य विशेषज्ञ[92] का कहना था कि किसी विदेशी को काम सौंपने में शामिल अन्य 6 देशों से पलायन करने वाले श्रमिकों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं हो सकता है। बहुपक्षीय संगठन[93] के एक प्रतिनिधि ने पूर्वी यूरोप के श्रमिकों हेतु बढ़ती प्रतिस्पर्धा और विशेष रूप से योग्यता मान्यता से संबंधित चुनौतियों पर प्रकाश डाला, जिनका कभी-कभी यूक्रेनियन और बेलारूसियों को सामना करना पड़ता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, पोलिश सरकार ने यूक्रेनी नर्सों के लिए ठोस पहल पर भी विचार किया है जो यूक्रेन में केवल

हाई स्कूल से स्नातक हैं और कौशल मान्यता के साथ समस्याओं का सामना करती हैं। हालाँकि, कई उत्तरदाताओं ने सांस्कृतिक एवं भाषाई समानताएँ बताईं। विशेष रूप से यूक्रेन और बेलारूस के लोग, पोलिश स्थानीय लोगों से स्पष्ट रूप से अलग नहीं दिखते हैं और उन्हें अक्सर चिकित्सा और आतिथ्य जैसे व्यवसायों में प्राथमिकता दी जाती है, जहां संचार महत्वपूर्ण है।

---

86 Most of the interviews for this brief took place prior to the beginning of the current political crisis in Ukraine. Section 4.1.2 reflects on the impact of this crisis, drawing on secondary literature and the views of respondents interviewed after the conflict began.

77 Interview Code IOM/2

88 Refer to Section 2.1 for a review of the Polish Declaration (an immigration policy for workers from 6 neighbouring countries, including Ukraine).

89 Ukraine Refugee Situation, Operational Data Portal, Retrieved from: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine.

90 Interview Code IOM/14

91 Interview Code IOM//15

92 Interview Code IOM/6

93 Interview Code IOM/5

एक बहुपक्षीय संगठन के एक प्रतिनिधि का कहना था कि हालांकि यूक्रेन, रूस और बेलारूस के लिए प्राथमिकता ऐतिहासिक संबंधों में निहित है, जॉर्जिया और अज़रबैजान जैसे देशों के साथ संबंध अधिक राजनीतिक है।[94]

एशिया में उभरते स्रोत देश: पड़ोसी देशों पर दस्तावेज़ी निर्भरता एवं प्राथमिकता के बावजूद, उत्तरदाताओं ने पोलैंड में आप्रवासन के बढ़ते विविधीकरण पर ध्यान खींचा। हालांकि, चीन और वियतनाम जैसे पूर्वी व दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से कुछ दशक पहले भी आप्रवासी आते थे, लेकिन अब उनकी भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जैसा कि भारत, नेपाल, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे अन्य उभरते एशियाई देशों में है। एक विशेषज्ञ ने हाल के दिनों में पोलैंड भर में एशियाई श्रमिकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि की बात कही। एक अन्य ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वियतनाम से आप्रवासन की सुविधा हेतु सरकार पर निजी क्षेत्र का अधिक (हालांकि असफल) दबाव रहा है; वियतनामी आप्रवासियों को पोलैंड में सबसे बड़ा गैर-यूरोपीय प्रवासी समूह माना जाता है।[95] एक नियोक्ता संगठन[96] के एक प्रतिनिधि ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एजेंसियां पोलैंड में अस्थायी श्रम सेवाएं प्रदान कर रही हैं जो वर्तमान में नेपाल और रूस के साथ काम करती हैं लेकिन भारत के साथ नहीं। एक बहुपक्षीय संगठन[97] के एक प्रतिनिधि ने बताया कि एशियाई आप्रवासियों को अक्सर मुश्किल कामकाजी परिस्थितियों वाले कुछ क्षेत्रों में लगाया जाता है, और पड़ोसी देशों के आप्रवासियों की तुलना में उनकी स्थिति बहुत अधिक सुरक्षित नहीं होती है। एक नियोक्ता संगठन प्रतिनिधि[98] का भी मानना था कि एशियाई आप्रवासियों को बदतर परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि उनके महासंघ का स्पष्ट रूप से कहना है कि विदेशी श्रमिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि बिना वर्क परमिट के अनौपचारिक परिस्थितियों में काम करने वाले लोगों के मामले में शोषण और कम वेतन का अनुभव होने का जोखिम अधिक होता है। उनके अनुसार, अन्य देश जो श्रमिक आप्रवासन के आसपास नीतिगत चर्चा में शामिल हुए हैं, उनमें मध्य एशियाई देश शामिल हैं। एक विशेषज्ञ के अनुसार, हालांकि, फिलीपींस स्वास्थ्य देखभाल और नर्सिंग के बारे में चर्चा में शामिल है, चेक गणराज्य जैसे देशों में कम वेतन और बेहतर संभावनाएं उन्हें आकर्षित करती हैं।[99]

कोविड-19 महामारी के दौरान भी बढ़ रहा आप्रवासन: सरकारी प्रतिनिधि[100] ने बताया कि 2020 की दूसरी तिमाही के दौरान थोड़ी गिरावट के बाद, तब से आप्रवासन बढ़ रहा है। अन्य सरकारी हितधारकों के डेटा से संकेत मिलता है कि सभी प्रकार के परमिट आवेदनों (75%) में युवाओं की संख्या अधिक है। महिला

प्रवासियों का प्रतिशत परमिट के प्रकार के आधार पर अलग-अलग जैसे वर्क परमिट (2021 में 25%), घोषणाएँ (2021 में 37%), और मौसमी वर्क परमिट (2021 में 64%) होता है। महामारी के दौरान कुछ क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए, विशेष रूप से सफाई सेवाएँ (यूक्रेनी महिलाओं के प्रभुत्व वाला क्षेत्र), क्योंकि उनके कार्यालय बंद हो गए थे। हालाँकि, महामारी के दौरान खाद्य एवं टेकअवे क्षेत्र में तेजी का अनुभव हुआ, जिससे मुख्य रूप से वहां काम करने वाले एशियाई प्रवासियों को लाभ हुआ।

5.1.3 आप्रवासन नीति पर अलग-अलग दृष्टिकोण

पड़ोसी देशों के लिए अधिमान्य नीति: अब तक उत्प्रवास के देश के रूप में, आप्रवासन एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकार ने अभी तक कोई व्यापक नीति नहीं बनाई है। हालाँकि, हितधारकों का कहना था कि इसका मसौदा कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले ही तैयार किया जा रहा था। विभिन्न हितधारक श्रेणियों के उत्तरदाताओं ने पोलिश आव्रजन नीति पर अलग-अलग विचार रखे, लेकिन सभी इस बात से सहमत थे कि देश पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देता है। कई हितधारकों ने घोषणा नीति का उल्लेख किया - एक ऐसी प्रणाली जिसमें नियोक्ताओं को 6 देशों (यूक्रेन, आर्मेनिया, जॉर्जिया, मोल्दोवा, बेलारूस, रूस) के नागरिकों को रोजगार देने हेतु स्थानीय वॉयोडशिप कार्यालय के पास "किसी विदेशी को काम पर रखने की घोषणा" दाखिल करने की अनुमति है। एक शोध विशेषज्ञ[101] का मानना था कि पोलैंड में प्रवासन नीति के संबंध में दूरदर्शिता का अभाव है और आप्रवासन का भविष्य क्या हो सकता है, इस पर आम तौर पर कोई सहमति नहीं है।

---

94 Interview Code IOM/7

95 Interview Code IOM/7

96 Interview Code IOM/13

97 Interview Code IOM/5

98 Interview Code IOM/13

99 Interview Code IOM/5

100 Interview Code IOM/1

101 Interview Code IOM/6

उन्होंने कहा कि इससे पहले भी 2012 जैसी नीति लागू करने की सरकार की कोशिशों को उसके बाद आई सरकारों ने रोक दिया था। हालाँकि, एक बहुपक्षीय संगठन के एक प्रतिनिधि का मानना था कि पोलिश आव्रजन नीति पहले केवल पड़ोसी देशों के लिए (घोषणा नीति के माध्यम से) रास्ते खोलकर अपने श्रम बाजार की कमी से निपटी है। वहीं, एक अन्य विशेषज्ञ[102] ने बताया कि पोलैंड की नीतियों को उदार एवं लचीली माना जा सकता है, लेकिन केवल छह पड़ोसी देशों के लिए और अल्पकालिक परिप्रेक्ष्य में। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि सरकार को एक बार वापसी-प्रवासन एवं कुछ कुशल पोलिश प्रवासियों को स्वदेश वापस लाने करने में गहरी दिलचस्पी थी। सरकारी प्रतिनिधियों[103] ने कहा कि घोषणा नीति अधिक दीर्घकालिक प्रवासन को आकर्षित करने का एक प्रयास था लेकिन वर्तमान में मौजूदा छह देशों से परे किसी भी नए देश पर विचार नहीं किया जा रहा है।

आप्रवासन के संदर्भ में जटिल नौकरशाही: कई हितधारकों ने आप्रवासन एवं वर्क परमिट में कानूनी जटिलताओं के बारे में बात की। 2007 के बाद से प्रवासन प्रक्रिया को आसान बनाने और घोषणाओं एवं मौसमी वर्क परमिटों की बढ़ती संख्या के बावजूद, नौकरशाही बाधाएँ से वो देश परेशान हो रहे हैं जो घोषणा नीति के अंतर्गत नहीं आते हैं। विशेषज्ञ उत्तरदाताओं ने यह भी बताया कि पोलैंड में ब्लू कार्ड की अधिक संभावना नहीं है क्योंकि यह मौजूदा राष्ट्रीय स्तर की आप्रवासन नीतियों की तुलना में प्रक्रिया आसान नहीं है। इसी तरह, उद्यमियों का आप्रवासन काफी जटिल प्रक्रिया है जिन्हें कई लोग अपनाना नहीं चाहेंगे। एक शोध विशेषज्ञ[104] ने बताया कि ब्लू कार्ड हेतु अर्हता प्राप्त करने वाले अप्रवासी आमतौर पर पोलैंड के बजाय अन्य पश्चिमी यूरोपीय देशों को प्राथमिकता दे सकते हैं। हालाँकि, एक अन्य विशेषज्ञ[105] ने क्राको जैसे उच्च स्किल वाले क्षेत्रों में ब्लू कार्ड की निरंतर प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला, जहां काफी संख्या में छात्र और संपन्न कॉर्पोरेट आते हैं। सरकारी प्रतिनिधियों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भविष्य में वर्क परमिट की अवधि को 36 महीने तक बढ़ाने की योजना है और पोलैंड वर्तमान में हर साल लगभग आधा मिलियन वर्क परमिट प्रोसेस करता है। उन्होंने कहा कि[106] सरकार वर्क परमिट के बजाय घोषणा चैनल के माध्यम से आप्रवासन को लेकर उत्सुक है। एक अन्य समस्या यह है कि ऐसे मामलों में जहां जॉब रोल बदल जाता है, वर्क परमिट हेतु फिर से आवेदन करना पड़ता है। सरकारी प्रतिनिधियों[107] ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वर्क परमिट मिलने के बाद (आमतौर पर औसतन 50-52 दिनों में), अप्रवासी श्रमिकों को निवास परमिट से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो एक स्वतंत्र प्रक्रिया है जिससे इंतजार का समय बढ़ता है। विदेशी श्रमिकों के लिए कानूनी नियमों को समझना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, हालांकि, कोविड-19 महामारी के दौरान, इन नियमों में ढील दी गई थी, सभी मौजूदा परमिटों को महामारी समाप्त होने तक बढ़ा दिया गया था। अनुसंधान विशेषज्ञों ने वीज़ा जारी करने से जुड़ी बाधाओं की ओर भी इशारा किया, एक ऐसी समस्या जो विशेष रूप से भारत को प्रभावित करती है और इसे खंड 5.2 में विस्तार से बताया गया है।

5.2 श्रमिक आप्रवासियों की उत्पत्ति के देश के रूप में भारत

इस खंड में, हम पोलैंड में श्रमिक आप्रवासन के प्रमुख देश के रूप में भारत के बारे में उत्तरदाताओं के विचारों पर बात करेंगे। यह भारतीय आप्रवासन की उभरती प्रकृति, मौजूदा रुझान एवं भारतीय श्रमिकों के लिए प्रासंगिक क्षेत्रों पर प्रकाश डालता है।

5.2.1 उल्लेखनीय और बढ़ते अल्पसंख्यक के रूप में भारतीय

भारत से श्रमिक आप्रवासन की प्रकृति: विभिन्न हितधारक श्रेणियों के कई उत्तरदाताओं ने आप्रवास के देश के रूप में भारत के बढ़ते महत्व पर अपने विचार व्यक्त किए। एशियाई देशों से आप्रवासन की एक सामान्य प्रवृत्ति भारत, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे देशों की ओर इशारा करती है, और भारतीयों की संख्या अपेक्षाकृत पोलैंड समाज में बढ़[108] रही ही।

102 Interview Code IOM/5
103 Interview Code IOM/1
104 Interview Code IOM/2
105 Interview Code IOM/4
106 Interview Code IOM/1
107 Interview Code IOM/9
108 Interview Code IOM/3

पोलैंड में श्रम मंत्रालय के सरकारी प्रतिनिधियों द्वारा साझा किए गए डेटा से पता चलता है कि 2021 में जारी किए गए वर्क परमिट में 3 प्रतिशत भारतीय थे, जो 2018 में 1.8 प्रतिशत से अधिक है, जिसमें सबसे अधिक परमिट अधिदेश अनुबंध (बिना पेंशन लाभ के अस्थायी) हेतु जारी किए गए थे। वास्तविक संख्या श्रमिकों, कारीगरों, वेल्डर, रसोइयों एवं डेटाबेस प्रशासकों जैसे जॉब प्रोफाइल में 2019 में 8052 से भारी वृद्धि भी दर्शाती है, जो 2021 में लगभग दोगुनी होकर 15305 हो गई है। बहुपक्षीय संगठनों में भारतीय अप्रवासियों के लिए महत्व के अन्य क्षेत्रों में विनिर्माण, प्रशासनिक एवं सहायता सेवाएँ, मशीन ऑपरेटर और फिटर और आईटी शामिल हैं। एक बहुपक्षीय संगठन के अनुसार, भारतीयों को दुनिया भर में भर्ती एजेंसियों वाली अंतरराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भी भर्ती किया जाता है।[109] 25-34 आयु वर्ग के अधिकांश पुरुष (94%) माज़ोविक्की, विल्कोपोलस्की और मालोपोलस्की जैसे प्रांतों में जाते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक वारसॉ और क्राको जैसे शहर भी भारतीय प्रवासियों के लिए जाने जाते हैं। साझा किए गए डेटा में इसका पता चलता है कि भारतीय मुख्य रूप से वर्क परमिट पर पोलैंड में प्रवास करते हैं, न कि मौसमी परमिट के माध्यम से, जिसकी सीमा 9 महीने की होती है। भारतीय प्रवासी पर काम करने वाले एक शोध विशेषज्ञ के अनुसार, भारतीय अप्रवासी भी देश भर के कई राज्यों से आते हैं, कई भाषाएँ बोलते हैं और विविध धार्मिक मूल के हैं।[110] शोध विशेषज्ञों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पोलैंड में भारतीय आप्रवासन हाल ही में बढ़ा है, खासकर पोलैंड के यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले एक शोध विशेषज्ञ द्वारा इसके पिछे दो प्रमुख कारण बताए गए।[111] सबसे पहला, पोलैंड की आर्थिक वृद्धि और प्रवासन दर अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में जीवन यापन की लागत अपेक्षाकृत कम लागत के साथ-साथ वेतन एवं श्रम बाजार के अवसरों को बढ़ाती है। दूसरा, पोलिश विश्वविद्यालय भारतीय छात्रों को प्रवेश देने में काफी सक्रिय हो रहे हैं। खाद्य वितरण क्षेत्र में भारतीय प्रमुख हैं। एक अन्य शोध विशेषज्ञ के अनुसार, वे योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा जैसे क्षेत्रों का लाभ उठाने हेतु भी तैनात हैं, जो पोलैंड में लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं।[112]

रेस्तरां क्षेत्र में भारतीय: केस स्टडी

एक शोध विशेषज्ञ, जिन्होंने पोलैंड में भारतीय प्रवासियों पर काफी कार्य किया है, ने कई भारतीयों द्वारा की गई व्यावसायिक पहलों का जिक्र किया है, खासकर आतिथ्य क्षेत्र में। विशेष रूप से भारतीय रेस्तरां तेजी से बढ़ रहे हैं, पिछले 10 वर्षों में हर सड़क पर कई रेस्तरां खुल गए हैं। पहले, इनमें से कई रेस्तरां अपना खर्च निकालने में भी संघर्ष करते थे और यहां पिज़्ज़ा जैसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ मिलते थे। हालाँकि, भारतीय भोजन का अनुभव लेकर ब्रिटेन से लौटने वाले पोलिश प्रवासियों ने भारतीय भोजन एवं भारतीय रेस्तरां की बढ़ती लोकप्रियता को प्रेरित किया है, जिससे उद्यमशीलता के अवसर सामने आए हैं।

छात्रों की भूमिका: कई हितधारकों ने भारतीय छात्र प्रवासन की भूमिका और यह पोलिश श्रम बाजार में भविष्य के एकीकरण हेतु एक प्रभावी चैनल कैसे हो सकता है, पर भी प्रकाश डाला। सरकारी हितधारकों[113] द्वारा साझा किया गया डेटा बताता है कि 2020 में, पोलिश विश्वविद्यालयों में 4.3 प्रतिशत अंतर्राष्ट्रीय

छात्र भारतीय (~3400) थे। सरकारी प्रतिनिधियों[114] ने भारतीय छात्र प्रवासन की भूमिका और यह पोलिश श्रम बाजार में भविष्य के एकीकरण हेतु एक प्रभावी चैनल कैसे हो सकता है, पर भी प्रकाश डाला। इस क्षेत्र के एक शोध विशेषज्ञ[115] ने बताया कि स्टडी रुट काफी प्रचलित है, जिसमें कई छात्र वीजा पर अंशकालिक और अंततः पूर्णकालिक (भारतीय छात्रों के लिए, मुख्य रूप से फूड डिलिवरी में) काम करने के लिए आते हैं।

---

109 Interview Code IOM/7
110 Interview Code IOM/4
111 Interview Code IOM/3
112 Interview Code IOM/3
113 Interview Code IOM/9
114 Interview Code IOM/1
115 Interview Code IOM/3

नौकरशाही संबंधी बाधाएँ और नीतिगत चुनौतियाँ: हितधारकों ने पोलैंड में भारतीय आप्रवासन में बाधा डालने वाले कारकों पर बात की। अनुसंधान विशेषज्ञों एवं निजी क्षेत्र के प्रतिनिधियों (नियोक्ता महासंघों और भर्ती एजेंसियों) ने विशेष रूप से भारत के लिए वीजा प्रोसेस करने की पोलिश दूतावासों की सीमित क्षमता पर प्रकाश डाला, जहां दिल्ली और मुंबई में स्थित मात्र दो दूतावास वीजा हेतु आवेदन करने वाले कई भारतीयों के लिए अपर्याप्त हैं।[116] ऐसे मामले सामने आए हैं कि भारतीय छात्रों को विश्वविद्यालय के उन कोर्स हेतु महीनों बाद तक वीज़ा नहीं मिल सका, जिनमें उन्हें प्रवेश मिल गया था और यहां तक कि ऐसे मामले भी सामने आए हैं, जहां वर्क परमिट जारी किए गए थे, लेकिन वीज़ा नहीं मिला। भर्ती उद्योग[117] के एक भारतीय हितधारक ने भी इस पर प्रकाश डाला कि पोलिश राजनयिक मिशनों को प्रोसेसिंग प्रक्रिया को अधिक कुशल बनाने हेतु भारत की प्रमाणित भर्ती कंपनियों के साथ काम करना चाहिए। एक शोध विशेषज्ञ के अनुसार, राजनीतिक विचार भी एक कारक हैं। उन्होंने कहा,[118] 2015 के बाद एवं शरणार्थी संकट के कारण, जनता की राय प्रवासियों के प्रति कुछ हद तक अच्छी नहीं है, और पोलिश सरकार अनौपचारिक रूप से आप्रवासन को सीमित करने हेतु कांसुलर कर्मचारियों को नहीं बढ़ाने की नीति का पालन करती है। यूरोपीय संघ के भीतर, पोलैंड प्रवासन पर अपने सख्त रुख हेतु जाना जाता है। एक सरकारी प्रतिनिधि[119] ने बताया कि भारतीय अप्रवासियों से जुड़े कोई ज्ञात जोखिम नहीं हैं। हालाँकि, उनके अनुसार, देश की उच्च प्रवासन क्षमता को जोखिम माना जा सकता है और सहयोग से आप्रवासन में तेजी आ सकती है। आव्रजन कानून[120] बैकग्राउंड से आने वाले एवं भारतीय समुदाय के प्रति अनुभव वाले एक विशेषज्ञ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय कागजी कार्रवाई के दौरान परेशान हो जाते हैं, और अक्सर इस प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु बिचौलियों के सहारे पर निर्भर रहते हैं। ऐसा मामले कम कौशल वाले श्रमिकों के संदर्भ में अधिक था, जिन्हें अंग्रेजी में भी मदद की आवश्यकता होती है। हालाँकि, हर बार जॉब रोल में बदलाव होने पर वर्क परमिट के लिए फिर से आवेदन से संबंधित मुद्दे आईटी जैसे उच्च कौशल क्षेत्रों में भारतीयों को परेशान करते हैं। विशेषज्ञ द्वारा बताया गया एक हालिया मामला एक भारतीय आईटी विशेषज्ञ का था जो अभी प्रबंधकीय पद पर कार्यरत है जो नई नौकरी की तलाश में है। हालाँकि नए परमिट हेतु आवेदन करते समय उसे देश में रहने की अनुमति देने के लिए हाल ही में नए नियम पारित किए गए हैं, लेकिन उसे ऐसा करना होगा। इसके विपरीत, जिन्होंने पोलैंड में पढ़ाई की है उन्हें ऐसी नौकरशाही बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता है।

भारतीय प्रवासी[121] के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले एक शोध विशेषज्ञ ने भारतीय एवं पोलिश सरकारों के बीच द्विपक्षीय समझौतों की संभावना पर बात की। उनके अनुसार, दोनों सरकारों के बीच अच्छे संबंधों और भारत में प्रवासन आकांक्षाओं को देखते हुए, इस कॉरिडोर में द्विपक्षीय समझौते से लाभ हो सकता है।

उन्होंने कहा कि हालांकि महामारी ने आवागमन प्रभावित हुआ है, लेकिन अब स्थिति सामान्य हो रही हैं, और वीजा प्रोसेसिंग जैसी नौकरशाही बाधाओं में तेजी लाने के प्रयास किए जाने चाहिए। एक उदाहरण जिसका जिक्र उन्होंने किया वह दिल्ली-वारसॉ के बीच सीधी फ्लाइट्स का था जो पूरी तरह से बुक होती थी लेकिन जिसे कोविड-19 महामारी के दौरान निलंबित कर दिया गया था। नियोक्ता महासंघ[122] के एक प्रतिनिधि ने यह भी कहा कि पोलैंड में निजी क्षेत्र भारत सरकार के साथ सहयोग हेतु खुला रहने की संभावना है, यह देखते हुए कि उन्हें श्रम की कमी का पता है। एक सरकारी प्रतिनिधि[123] ने कहा कि प्रवासन पर द्विपक्षीय समझौतों का एक महत्वपूर्ण कारक "अवैध आप्रवासियों" की वापसी पर देश का सहयोग है। उन्होंने कहा कि पोलैंड को भारतीयों द्वारा वीजा अवधि से अधिक समय तक रहने या अन्यथा ऐसे नियमों का उल्लंघन करने के ज्यादा मामले नहीं है और वापसी पर भारत सरकार के साथ सहयोग करने में कोई गंभीर बाधाएं नहीं दिखती हैं। भारत[124] में एक क्षेत्रीय हितधारक ने बताया कि केरल जैसे भारतीय राज्यों को पोलैंड जैसे देशों से भर्ती अनुरोध प्राप्त होते हैं, लेकिन संस्थाओं से सीमित समर्थन के कारण अक्सर उन पर अमल करने में असमर्थ होते हैं। उन्होंने भविष्य में ऐसे भर्ती अनुरोधों का जवाब देने हेतु भारत सरकार के साथ काम करने की इच्छा का भी जिक्र किया।

---

116 Interview Code IOM/3
117 Interview Code IOM/11
118 Interview Code IOM/3
119 Interview Code IOM/10
120 Interview Code IOM/8
121 Interview Code IOM//3
122 Interview Code IOM/13
123 Interview Code IOM/10
124 Interview Code IOM/12

पारगमन देश के रूप में पोलैंड: द्वितीयक लिटरेचर का जिक्र करते हुए, एक अनुसंधान संगठन के प्रतिनिधि,[125] भारतीय प्रवासी विशेषज्ञ, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय एक अत्यधिक गतिशील समूह हैं, जो विशेष रूप से अन्य पश्चिमी देशों में प्रवास की उम्मीद रखते हैं। एक अन्य ने पोलैंड में भारतीय छात्रों के ऐसे मामलों की ओर इशारा किया जो पढ़ाई छोड़कर काम हेतु यूरोपीय संघ में जाने का विकल्प चुनते हैं।[126]

5.3 विदेशी कामगारों का एकीकरण

यह खंड पोलैंड में विदेशी श्रमिकों के एकीकरण अनुभवों, चुनौतियों एवं संभावनाओं पर केंद्रित है। इस खंड में देश में राष्ट्रीय स्तर की एकीकरण नीति की कमी, एकीकरण नीति में बहुसंस्कृतिवाद की भूमिका एवं विशेष रूप से भारतीय समुदाय की एकीकरण क्षमता पर बात की गई है।

5.3.1 स्थानीय चैनलों के माध्यम से पूरक राष्ट्रीय नीति का अभाव

सभी हितधारक श्रेणियों के कई उत्तरदाताओं ने पोलैंड की एकीकरण नीति की कमी एवं अप्रवासियों के रोजमर्रा के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थानों की अविकसित प्रकृति पर बात की। एक शोध विशेषज्ञ[127] ने बताया कि एकीकरण योजनाएं आम तौर पर शरणार्थियों के लिए उपलब्ध होती हैं, लेकिन श्रमिक आप्रवासी एवं उनके परिवारों को आमतौर पर ऐसा कुछ नहीं मिलता है। सरकारी प्रतिनिधियों[128] का मानना था कि एकीकरण की चुनौतियाँ रोजगार, कार्य, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सामाजिक समर्थन एवं आवास सहित जीवन के सभी पहलुओं में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि एकीकरण

के लिए संस्थागत बुनियादी ढाँचा अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं है। शोध विशेषज्ञों ने बताया कि राष्ट्रीय नीति के अभाव में, शहरों में स्थानीय स्तर की पहल एवं गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, खासकर स्कूलों तक पहुंचने वाले परिवारों, स्थानीय नौकरशाही को नेविगेट करने एवं जानकारी प्रदान करने में।[129] एक अन्य शोध विशेषज्ञ ने पोलैंड को विविध आप्रवासी समुदायों के साथ आने वाले बहुसंस्कृतिवाद को अपनाने की आवश्यकता पर बद दिया। उनके अनुसार, देश यूक्रेन और बेलारूस के सांस्कृतिक रूप से समान आप्रवासियों का आदी रहा है, इसलिए इसे तेजी से विविध राष्ट्रों से आने वाले लोगों को समायोजित करने हेतु अपनी एकीकरण नीतियों में बदलाव लाना होगा।[130]

एक अन्य विशेषज्ञ ने आप्रवासी परिवारों की बदलती प्रकृति पर प्रकाश डाला, विशेष रूप से दूसरी और तीसरी पीढ़ी के आप्रवासी जो पोलिश में पले-बढ़े हैं लेकिन एकीकृत नहीं हैं।[131] एक सरकारी प्रतिनिधि[132] ने राष्ट्रीय श्रम निरीक्षणालय के काम की ओर इशारा किया, जो विदेशी श्रमिकों को अंग्रेजी सहित उनकी भाषाओं में व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों के अधिकारों एवं श्रम कानून के बारे में जानकारी प्रदान करता है। श्रमिकों को संस्था के पास शिकायत एवं कानून उल्लंघन दर्ज करने का भी अधिकार होता है।

5.3.2 भारतीयों के लिए सांस्कृतिक समानताएं और एकीकरण क्षमता

उत्तरदाताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बढ़ती संख्या के साथ, भारतीय अब पोलैंड में एक महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आप्रवासी समुदाय हैं। एक शोध विशेषज्ञ[133] ने बताया कि भारतीयों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है और उन्हें ज्यादा भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके अनुसार, भारतीयों में सांस्कृतिक समानता भी बहुत अधिक देखी जाती है, विशेषकर परिवार, संस्कृति एवं परंपराओं में पोलिश मूल्यों के संबंध में। एकीकरण में भारतीय प्रवासी संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। विगत कुछ वर्षों में, खेल एवं संस्कृति से जुड़े संघ, साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से, नए आगमन का समर्थन करने के लिए उभरे हैं। हालाँकि, पोलैंड में आप्रवासन के प्रति दृष्टिकोण के विश्लेषण से पता चलता है कि पोलिश समाज जर्मनी एवं फ्रांस जैसे यूरोप के अन्य पारंपरिक गंतव्य देशों की तरह आप्रवासियों के प्रति उतना इच्छुक नहीं रहा है। जैसा कि पहले बताया गया है, एमआईपीईएक्स पर पोलैंड का स्कोर 2014 के बाद से कम हो गया है, और जर्मनी एवं फ्रांस में 12-13 प्रतिशत की तुलना में पोलैंड के केवल 4 प्रतिशत लोग आप्रवासन को देश हेतु महत्वपूर्ण मानते हैं।[134] नीचे दिए गए खंड में, हमने हाल के दिनों में भारतीय प्रवासी के विभिन्न सदस्यों के कुछ नकारात्मक अनुभवों पर भी प्रकाश डाला है।

125 Interview Code IOM/4

126 Interview Code IOM/3

127 Interview Code IOM/2

128 Interview Code IOM/9

129 Refer to Section 3.2 for a secondary overview of local-level integration initiatives in Poland.

130 Interview Code IOM/4

131 Interview Code IOM/6

132 Interview Code IOM/9

133 Interview Code IOM/3

134 Observatory of Public Attitudes to Migration (OPAM), 2021, Retrieved from https://migrationpolicycentre.eu/opam/ (based on Eurobarometer data).

5.3.3 एकीकरण की भाषा

लगभग हर हितधारक ने मध्यम से दीर्घावधि में प्रभावी एकीकरण हेतु पोलिश भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात की। एक शोध विशेषज्ञ[135] ने स्कूली शिक्षा प्रणाली में इसकी विशेष आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जहां अधिकांश शिक्षक केवल पोलिश भाषा में बात करते हैं। हालाँकि, कुछ शहरों में, अंग्रेजी में पाठ्यक्रम तेजी से बढ़ रहे हैं। एक सरकारी प्रतिनिधि के अनुसार,[136] पोलिश भाषा सामाजिक, व्यावसायिक एवं संस्थागत माहौल में रोजमर्रा की जिंदगी हेतु महत्वपूर्ण है। अप्रवासियों, विशेषकर बच्चों के लिए भाषा प्रशिक्षण की सुविधा हेतु राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर (निजी क्षेत्र सहित) पहल की गई हैं। बहुपक्षीय संगठन[137] के एक प्रतिनिधि ने बताया कि भारतीय उन क्षेत्रों में काम करते हैं जहां भाषा उतनी प्रासंगिक नहीं है। हालाँकि, उनके लिए भी, रोजमर्रा की जिंदगी में भाषा की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। उनके अनुसार, यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो दीर्घकालिक निवास परमिट चाहते हैं, जहां बी1 स्तर तक पोलिश का ज्ञान एक अनिवार्य शर्त है।

5.4 प्रवासी भारतीयों के विचार

"अगर भारतीय छात्र भाषा के मामले में चुनौती के लिए तैयार हैं, तो वे पोलैंड आने हेतु आवेदन कर सकते हैं।" - ***प्रवासी साक्षात्कार 1***

"पोलिश भाषा के ज्ञान के बिना भी पोलैंड में रहा जा सकता है, कम से कम देश के कुछ हिस्सों में। लेकिन, अगर कोई यहां लंबे समय तक रहने का सोच रहा है, तो पोलिश भाषा सीखना अनिवार्य है। ***प्रवासी साक्षात्कार 5***

भाषाई और सांस्कृतिक मतभेद: कुल मिलाकर, साक्षात्कार में शामिल प्रवासी सदस्यों को पोलैंड में जिन भाषाई एवं सांस्कृतिक मतभेदों का सामना करना पड़ा, उन पर उनके अलग-अलग विचार हैं। हालाँकि, अधिकांश ने रोजमर्रा की जिंदगी में भाषा सीखने के महत्व को रेखांकित किया, भले ही उसकी शिक्षा अंग्रेजी में हो। पर्यटन में हाल ही में स्नातक किए हुए एक छात्र जिसकी अब नौकरी लग गई है, का मानना था कि यूरोप एवं यूरोपीय संघ के बीच में होने के भौगोलिक लाभों के बावजूद, पोलैंड उन लोगों के लिए सबसे अच्छा गंतव्य नहीं है जो कभी विदेश नहीं गए हैं। हालाँकि, उनका अनुभव सकारात्मक और सशक्त रहा है, और वह फिलहाल पोलैंड में बसने का सोच रहे हैं।

एक अन्य प्रवासी सदस्य, जो लगभग तीन दशकों से पोलैंड में रह रहे हैं, ने भारतीयों की अपेक्षाकृत फॉस्ट, तेज जिंदगी की तुलना धीमी, अधिक सुविचारित यूरोपीय जीवनशैली से की। उनका मानना था कि यदि भारतीयों को पोलिश के स्थानीय लोगों के साथ काम करना तथा मेलजोल बढ़ाना है तो उन्हें सामन्जस्य बैठाना होगा। जिन लोगों ने पोलैंड में पढ़ाई की है, वे मुख्य रूप से नौकरशाही संबंधित मामलों में अपने विश्वविद्यालयों से प्राप्त समर्थन को लेकर सकारात्मक थे, लेकिन उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि वारसॉ, ग्दान्स्क एवं क्राको जैसे बड़े शहर प्रवासियो के लिए अधिक अनुकूल हैं। वारसॉ में एक भारतीय छात्र ने भी छात्रों के लिए उपलब्ध व्यापक अंशकालिक काम के अवसरों की सराहना की, प्रमुख सूचनार्थी साक्षात्कारों में इस बिंदु पर प्रकाश डाला गया।

"विगत 4 वर्षों में श्रम की भारी कमी है, और हम पोलैंड के नागरिकों के वापस आने के संदर्भ में बहुत अधिक हलचल देख सकते हैं, यूक्रेनियन भी आ रहे हैं और पिछले 4-5 वर्षों में, बहुत सारे भारतीय भी आए हैं, यह एक आश्चर्यजनक था। वास्तव में एशियाई देशों से श्रमिक एवं ब्लू कॉलर तथा व्हाइट कॉलर हासिल करने की भारी मांग है।" –

प्रवासी साक्षात्कार 2

"मुझे नहीं लगता कि यूरोप, सामान्य तौर पर, भारतीयों के लिए अच्छा गंतव्य है - वहाँ बहुत अधिक भाषा एवं सांस्कृतिक बाधाएँ हैं, और बहुत अधिक पूर्वाग्रह एवं नस्लवाद है। भारत में, हमारी पूर्व धारणा है कि इन देशों में अपराध बहुत कम है और जीवन स्तर अच्छा है, लेकिन सच तो यह है कि यूरोप में रहना बहुत महंगा है, और भेदभाव एवं नस्लवादी अपराध आम हैं। - प्रवासी साक्षात्कार 4

135 Interview Code IOM/2

136 Interview Code IOM/9

137 Interview Code IOM/7

अवसर मौजूद हैं, लेकिन नौकरशाही एवं भेदभाव संबंधी चुनौतियाँ हैं: व्यापारिक समुदाय का अनुभव वाले साक्षात्कारकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पोलैंड का आर्थिक विकास अप्रवासियों के लिए कई अवसर पेश करता है। भारतीय आप्रवासन से आईटी, व्यवसाय, फार्मास्यूटिकल्स एवं अनुसंधान जैसे क्षेत्रों को बहुत लाभ होगा। हालाँकि, कई चुनौतियाँ भी हैं। कई साक्षात्कारकर्ताओं ने वीज़ा से लेकर निवास परमिट तक कागजी कार्रवाई की चुनौतियों पर बात की। हाल ही में पोलैंड में काम करना शुरू करने वाली एक स्नातक ने अपनी पढ़ाई के दौरान समय पर वीज़ा मिलने, निवास परमिट के लिए आवेदन करने एवं फिर वर्क परमिट के लिए आवेदन करने में आने वाली कुछ नौकरशाही बाधाओं पर प्रकाश डाला। एक मौजूदा छात्र ने निवास परमिट के लिए लंबे समय तक इंतजार करने की बात कही, जिसके बिना वह पोलैंड नहीं छोड़ सकता। कभी-कभी, नौकरशाही से छुटकारा पाने के लिए वकील की मदद लेना सबसे तेज़ और आसान तरीका लगता है। हाल ही में स्नातक हुए एक अन्य छात्र को विश्वविद्यालय की मदद और पोलिश नौकरशाही को लेकर बुरे अनुभव से गुजरना पड़ा। अधिकांश साक्षात्कारकर्ताओं का कहना था कि पोलैंड प्रवासियों के लिए पूरी तरह से अच्छा नहीं है, हालांकि युवा पीढ़ी मित्रवत एवं अधिक ओपन है। एक साक्षात्कारकर्ता को उस वक्त नस्लवाद का अनुभव करना पड़ा जब मकान मालिकों ने उसे कोविड-19 महामारी के दौरान घर देने से इनकार कर दिया, जिससे वह कुछ समय तक व्यावहारिक रूप से बेघर हो गया। बड़े पैमाने पर प्रवासी भारतीयों से जुड़े एक भारतीय ने पोलैंड के भारतीय समुदाय की एक हालिया पहल पर प्रकाश डाला, जिसमें भारतीय समुदाय से नस्लवाद के 1000 से अधिक मामलों पर डेटा एकत्र किया गया और राजदूत के साथ साझा किया गया। यह संगठन पोलैंड में भारतीयों का समर्थन करने हेतु स्थानीय सरकार, पोलिश सांख्यिकी कार्यालय, सीमा रक्षक और दूतावासों के साथ मिलकर काम करता है।

"यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, मुझे लगता है कि पिछले 25 से 30 वर्षों में, मैंने किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की पोलैंड की बहुत उच्च स्तरीय यात्रा नहीं देखी है। ये उच्च स्तरीय यात्राएं हमेशा विभिन्न स्तरों पर संबंधों को बढ़ावा देने में मदद करती हैं, चाहे वह व्यावसायिक हो या सांस्कृतिक हो। और इससे रिश्तों को सही भावना में रखने में मदद मिलती है।" - ***प्रवासी साक्षात्कार 2***

भारत सरकार से उच्च-स्तरीय जुड़ाव की आवश्यकता: दो साक्षात्कारकर्ता जो पोलैंड में काफी समय से रह रहे हैं और प्रवासी कल्याण से जुड़े हुए हैं, ने भारतीय सरकारी हितधारकों से संस्थागत जुड़ाव की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। अप्रैल 2017 में भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम. हामिद अंसारी का पोलैंड में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कई अन्य महत्वपूर्ण राजनयिक यात्राएं भी हुई हैं। उदाहरण के लिए, पोलैंड के राष्ट्रपति के राज्य सचिव एवं कैबिनेट के प्रमुख क्रिज़िस्तोफ़ स्ज़ेर्सकी ने जनवरी 2019 में भारत का दौरा किया। इसके अलावा, अगस्त 2019 में, वर्तमान विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने आधिकारिक यात्रा की। इस तरह की और यात्राओं से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। एक साक्षात्कारकर्ता ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि पोलैंड को नौकरशाही बाधाओं का मुकाबला करने हेतु अन्य भारतीय शहरों में अतिरिक्त वाणिज्य दूतावास खोलने पर विचार करना चाहिए। दोनों उत्तरदाताओं ने इस बात पर बल दिया कि वे और वे संगठन जिनसे वो जुड़े हुए हैं (पोलैंड में भारतीय समुदाय, इंडो-पोलिश चैंबर ऑफ कॉमर्स) पोलैंड में भारतीय समुदाय के कल्याण हेतु भविष्य में भारत सरकार के साथ काम करना चाहते हैं।

"अगर सरकारी स्तर पर बातचीत होती है, तो भारतीयों को अक्सर लोगों को धोखा देने वाले अनौपचारिक एजेंटों से बचाने हेतु एक प्रणाली बनाना आवश्यक है। क्योंकि अप्रवासन का नियमित माध्यम धीमा है,

लोग हताश हो जाते हैं तथा उन्हें अनियमित एजेंटों को बहुत अधिक पैसा देना पड़ता है। - ***प्रवासी साक्षात्कार 4***

"पोलैंड में प्रवास की एक बड़ी समस्या अपंजीकृत, अनौपचारिक एजेंटों का होना है जो प्रवासियों को फर्जी नौकरी की पेशकश देकर या वीजा तथा अन्य प्रक्रियाओं के लिए बड़ी रकम लेकर धोखा देते हैं। इस प्रकार के मुद्दों को प्रवासी भारतीयों द्वारा हल नहीं किया जा सकता है, हालांकि हम नियमित रूप से लोगों को केवल पंजीकृत भर्तीकर्ताओं एवं एजेंसियों से ही ऐसा करने के लिए कहकर प्रयास करते हैं, लेकिन प्रवासियों को इससे बचाने के लिए किसी प्रकार का संस्थागत तंत्र बहुत मददगार होगा। - ***प्रवासी साक्षात्कार 5***

इंडो-पोलिश कॉरिडोर में सक्रिय अनियमित चैनल, अनौपचारिक एजेंसियां: दो साक्षात्कारकर्ताओं ने अनौपचारिक, अनियमित एजेंसियों की गतिविधियों पर प्रकाश डाला जो कुछ महत्वाकांक्षी भारतीय प्रवासियों को खतरे में डालती हैं। ये एजेंसियां अक्सर प्रवासियों को फर्जी नौकरी की पेशकश करके धोखा देती हैं और परमिट व वीजा के लिए बड़ी रकम मांगती हैं। जो लोग जाने के लिए बेताब हैं और लंबे इंतजार से इंतजारक कर हैं वे अक्सर यही विकल्प चुनते हैं। दोनों ने इस मुद्दे पर सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

6 | निष्कर्ष

6.1 प्रमुख निष्कर्ष

- **बुढ़ी होती जनसंख्या और पोलिश नागरिकों के दूसरे देशों में प्रवास** के साझा प्रभाव के कारण पोलैंड को विभिन्न क्षेत्रों में श्रम की कमी का सामना करना पड़ रहा है। कृषि, निर्माण, आतिथ्य, परिवहन, रसद एवं देखभाल जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ आईटी और स्वास्थ्य सेवा जैसे उच्च कौशल की आवश्यकता वाले उद्योगों को ऐसी कमी का सामना करना पड़ रहा है जो पड़ोसी देशों के अप्रवासियों ने पूरी की हैं।

- पोलिश श्रम बाज़ार आंशिक रूप से खुल गया है, विशेषकर पड़ोसी देशों से मौसमी कार्यों के लिए। **यूक्रेन एवं बेलारूस से सबसे अधिक प्रवासी आते थे,** लेकिन मोल्दोवा, जॉर्जिया और रूस सहित अन्य देश भी महत्वपूर्ण हैं। एशियाई देशों के संदर्भ में उत्तरदाताओं ने कहा कि पिछले कुछ दशकों में **चीन और वियतनाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं और नेपाल, भारत और बांग्लादेश जैसे उभरते देश भी महत्वपूर्ण रहे हैं।** हालाँकि, यूक्रेनी प्रवासी श्रम बाजार में और मौजूदा श्रम की कमी को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और निभाते रहेंगे। यूक्रेन में हालिया युद्ध की वजह से पोलैंड में यूक्रेनियन की संख्या तेजी से बढ़ी (मार्च 2022 के अनुमान के अनुसार 2.3 मिलियन) है। **हितधारकों को उम्मीद है कि इससे अन्य देशों से आप्रवासन प्रभावित होगा** क्योंकि पोलैंड के पास स्थानीय आबादी के साथ मजबूत सांस्कृतिक एवं भाषाई संबंधों के साथ अच्छी संख्या में श्रम शक्ति होगी। हालाँकि, अभी भी कुछ सवालों के जवाब तलाशने की जरूरत है कि **क्या नई यूक्रेनी श्रम शक्ति पोलैंड में वर्तमान में मौजूद श्रम की कमी को पूरा कर सकेगी।** हालांकि, यूक्रेनियन अब पोलैंड में श्रम की कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकते हैं, लेकिन यह अभी भी समझने की कोशिश की जा रही है कि क्या यह श्रम बल स्वास्थ्य सेवा एवं लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों में काफी समय से चली आ रही कमी को दूर कर सकता है।

- **पोलैंड में भारत का अप्रवासी समुदाय अपेक्षाकृत काफी छोटा है**, लेकिन व्यवसाय (होलसेल, आतिथ्य) एवं शिक्षा क्षेत्र दोनों में इसकी जड़ें मजबूत हैं। माध्यमिक साहित्य एवं प्राथमिक साक्षात्कारों में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि भारतीय थोक एवं खुदरा व्यवसायों, रेस्तरां और खानपान के साथ-साथ आईटी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ समय से विनिर्माण, निर्माण एवं प्रशासनिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अर्ध-कौशल और अस्थायी पद भी भारतीयों को मिलने लगे हैं, और पिछले तीन वर्षों में जारी किए गए परमिटों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। हालाँकि, यूक्रेनी शरणार्थियों की नई आमद को देखते हुए, आईटी **(जहां भारतीयों को आमतौर पर अच्छा माना जाता है और पसंद किया जाता है)** और **व्यवसाय (जहां भारतीयों ने खुद को कुछ हद तक स्थापित कर लिया है)** जैसे क्षेत्र भविष्य में अच्छे विकल्प हो सकते हैं। छात्रों का प्रवासन एक महत्वपूर्ण मार्ग बना हुआ है, कई हितधारक पोलैंड में पढ़ने वाले भारतीयों की बढ़ती संख्या और खाद्य वितरण जैसे क्षेत्रों में छात्रों की नौकरियां लेने पर प्रकाश डाल रहे हैं। **अंग्रेजी शिक्षा की उपलब्धता और छात्रों के लिए अंशकालिक काम के नियमों में छूट को देखते हुए,** यह पोलैंड में भारतीय आप्रवासन और श्रम बाजार एकीकरण हेतु भविष्य का एक महत्वपूर्ण अवसर है।

- कई हितधारकों ने पहचाना कि मुख्य चुनौती पोलैंड की है **अधिक सरकारी नीति की आवश्यकता.** आप्रवासन के प्रति जनता के अपेक्षाकृत नकारात्मक रवैये के कारण, **सरकार** निजी क्षेत्र और नियोक्ताओं के बीच बढ़ती श्रम की कमी पर कार्रवाई करने में धीमी रही है प्रकाश डाला है. नियोक्ता

समूहों के दबाव के कारण हाल के वर्षों में कुछ छूट मिली है, लेकिन एक **व्यापक प्रवासन नीति को अभी तक आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं दिया गया है।** यूक्रेनी शरणार्थी के बाद से अब उम्मीद है कि जनसंख्या मौजूदा कुछ कमी से निपटने में मदद करेगी, **सरकारी स्तर पर अन्य आप्रवासी समूहों के लिए ऐसी नीति जल्द ही वास्तविकता नहीं बन सकती है।** हालांकि हितधारक द्विपक्षीय जुड़ाव की संभावना के बारे में आशावादी थे, **निजी क्षेत्र के संघों** और भर्ती बिरादरी के माध्यम से सहयोग प्राप्त करना सबसे उपयोगी हो सकता है। श्रम बाज़ार सुधार को आगे बढ़ाने में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है। यह श्रमिकों की कमी से भी सबसे अधिक प्रभावित है और विदेशी श्रमिकों के आप्रवासन के लिए पैरवी कर रहा है। वे भारत जैसे स्रोत देशों के लिए **द्विपक्षीय सहयोग के लिए** एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करते हैं ।

- कई हितधारकों का मानना था कि मुख्य चुनौती पोलैंड की **अधिक सरकारी नीति की आवश्यकता** है। **आप्रवासन के प्रति जनता के नकारात्मक रवैये के कारण, सरकार बढ़ती श्रम की कमी पर कार्रवाई करने में सुस्त रही** है, जिसे निजी क्षेत्र और नियोक्ताओं ने उजागर किया है। नियोक्ता समूहों के दबाव के कारण हाल के वर्षों में कुछ छूट मिली है, लेकिन व्यापक प्रवासन नीति को अभी तक आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं दिया गया है। चूंकि **यूक्रेनी शरणार्थियों से अब मौजूदा कमी का मुकाबला करने में कुछ मदद मिलने की उम्मीद है,** इसलिए सरकारी स्तर पर अन्य आप्रवासी समूहों के लिए ऐसी नीति में कुछ और समय लग सकता है। **हालांकि, हितधारक द्विपक्षीय जुड़ाव की संभावना को लेकर आशावादी** थे, लेकिन निजी क्षेत्र के संघों एवं भर्ती कंपनियों के माध्यम से सहयोग प्राप्त करना सबसे उपयोगी हो सकता है। श्रम बाज़ार सुधार को आगे बढ़ाने में निजी क्षेत्र महत्वपूर्ण रहा है। यह श्रमिकों की कमी से भी सबसे अधिक प्रभावित है और विदेशी श्रमिकों के आप्रवासन की पैरवी कर रहा है। **वे भारत जैसे देशों के लिए द्विपक्षीय सहयोग का एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करते हैं।**

6.2 सीमाएँ

- पोलैंड यूक्रेन युद्ध के समय प्रतिक्रिया देने वाले सबसे पहले देशों में से एक है, जिसने अब तक 3 मिलियन से अधिक यूक्रेनी शरणार्थियों को शरण दी है। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी सीमा यह है कि अधिकांश साक्षात्कार संकट की शुरुआत से पहले हुए थे। इसलिए हितधारकों ने इस बात पर सीमित विचार की व्यक्ति किए हैं कि उभरती भू-राजनीतिक स्थिति भारतीय आप्रवासन को कैसे प्रभावित करेगी। हालाँकि, इससे सरकारी हितधारकों (जो अब साक्षात्कार देने हेतु काफी बहुत व्यस्त हैं) का साक्षात्कार करना संभव हो गया है और उन्हें विशेष रूप से भारतीय समुदाय पर अपना विचार देने के लिए कहना संभव हो गया है।

- इस रिपोर्ट कि ट्रेड यूनियनों के विचारों को रखने के संदर्भ में भी कुछ सीमाएं है, जो प्रोजेक्ट टीम द्वारा किए गए ईमेल और टेलीफोन का अक्सर जवाब नहीं दे रहे थे। भारतीय प्रवासियों के विचार भी कुछ हद तक सीमित हैं। हालाँकि, हमारे दो उत्तरदाता प्रवासी संगठनों से निकटता से जुड़े हुए थे और उन्होंने भारतीय समुदाय के अनुभवों का अधिक विस्तृत विवरण दिया था।

परिशिष्ट

*रिपोर्ट में दिए गए निष्कर्ष कुल **21 प्रमुख सूचनार्थी साक्षात्कारों** (7 महिला, 14 पुरुष) - पोलैंड में स्थित नौ संस्थानों के 15 विशेषज्ञ, 5 प्रवासी साक्षात्कार और 2 भारतीय केआईआई से लिए गए हैं।*

	हितधारक	हितधारक श्रेणी
1.	परिवार एवं सामाजिक नीति मंत्रालय (श्रम प्रवासन, सांख्यिकी और विधान पर 3 विशेषज्ञ आईओएम/1)	**सरकार**
2.	ऑफिस फॉर फॉरेनर्स, पोलैंड सरकार (आईओएम/9)	
3.	आंतरिक एवं प्रशासन मंत्रालय (आईओएम/10)	
4.	परिसंघ लेविथान (आईओएम /13)	**नियोक्ता संगठन, व्यापार यूनियन**
5.	इंडो-पोलिश चैंबर ऑफ कॉमर्स (आईओएम/14)	
6.	प्रवासन अनुसंधान केंद्र (आईओएम/2)	**अनुसंधान संगठन, गैर सरकारी संगठन, विशेषज्ञ**
7.	अंतर्राष्ट्रीय मामलों का पोलिश संस्थान (आईओएम /3)	
8.	क्राको विश्वविद्यालय (आईओएम /4)	
9.	सार्वजनिक मामलों का संस्थान (आईओएम/6)	
10.	आव्रजन संबंधी वकील (व्यक्तिगत विशेषज्ञ, भारत पर केंद्रित (आईओएम/8)	
11.	समाज कल्याण केंद्र, वोला ज़िला, वारसा (आईओएम/15)	
12.	आईसीएमपीडी पोलैंड (आईओएम/5)	**बहुपक्षीय**
13.	आईओएम पोलैंड (आईओएम/7)	
14.	5 छात्र और कामकाजी पेशेवर	**भारतीय प्रवासी**
15.	भारतीय कार्मिक निर्यात संवर्धन परिषद	

(आईपीईपीसीआईएल) (आईओएम/11)

		भारतीय हितधारक
16.	अनिवासी केरलवासी संघ (एनओआरकेए), केरल सरकार (आईओएम/12)	

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ

सहयोगकर्ता